● वर्ष-5

● अंक-164

रायपुर, रविवार
22 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› भाजपा समेत विभिन्न संगठनों...

मुख्यमंत्री साय का भावुक संदेश

माँ केवल शब्द नहीं, जीवन का सबसे पवित्र अहसास

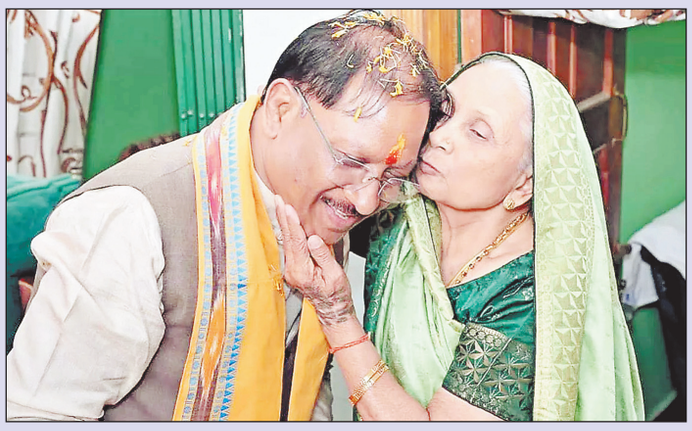

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भावुक और प्रेरक संदेश साझा करते हुए माँ के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि माँ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संवेदना, भावना और जीवन का सबसे पवित्र अहसास है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में माँ को जीवन रूपी उपवन की खुशबू बताते हुए कहा कि माँ लोरी की मधुरता, स्नेह की कोमल थाप, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने पूज्य माताजी के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि माँ के स्नेह, संस्कार और शुभाशीष से लोकमंगल एवं जनसेवा के उनके संकल्प को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि जीवन में मिले संस्कार और मूल्य उनके सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि माँ द्वारा दिखाए गए सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के मार्ग पर चलते हुए वे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के सुख, सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जनसेवा ही उनका सर्वोच्च लक्ष्य है और इसी भावना के साथ उनके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस भावुक संदेश ने आमजन के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। सामाजिक और राजनीतिक हलकों में उनके इस संदेश को पारिवारिक मूल्यों, संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जा रहा है।

जन्मदिन पर सेवा का संदेश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने 62वें जन्मदिन के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की तथा रक्तदाताओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री के 62वें जन्मदिन के अवसर पर अल्फा ग्लोब फाउंडेशन, रायपुर तथा शिवनाथ ब्लड सेंटर द्वारा 62 लोगों के रक्तदान की विशेष व्यवस्था की गई थी।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान महादान है और यह मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं, प्रसव एवं गंभीर बीमारियों के दौरान जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में रक्तदान मरीजों के जीवन में नई आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए हैं।

भारत-ब्राजील संबंधों में नई ऊर्जा

20 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य

नईदिल्ली।। नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ उनकी बातचीत से दोनों देशों की रणनीति साझेदारी में नयी ऊर्जा आयी है और दोनों पक्षों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर (करीब 1,814.5 अरब रुपये) के पार ले जाने की प्रतिबद्धता जतायी है।

श्री मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आये श्री दा सिल्वा के साथ शनिवार को यहां द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में कहा कि श्री दा सिल्वा की यात्रा ने भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी में नया जोश भर दिया है।सिल्वा की यात्रा ने हमारी रणनीतिक साझेदारी में नयी ऊर्जा का संचार किया है। ब्राजील लातिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हम अगले पांच वर्षों में अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर (करीब 1,814.5 अरब रुपये) से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा व्यापार केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह विश्वास का प्रतिबिंब है। मोदी ने कहा कि दा सिल्वा के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इन संबंधों में बढ़ते भरोसे को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत-मर्कोसुर व्यापार समझौते का विस्तार आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। उन्होंनेक कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कंम्पयूटर,सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हम दोनों देश मानते हैं कि प्रौद्योगिकी समावेशी होनी चाहिए और के इसे साझा प्रगति

के पुल की तरह काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा सहयोग हमारे संबंधों का एक मजबूत स्तम्भरहा है। हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा, इथेनाल मिश्रमण, सतत विमान ईंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में भी सहयोग को और अधिक गति दे रहे हैं। ग्लोबल बायो-फ्यूल अलायंस में ब्राजील की सक्रिय भागीदारी, हरित भविष्य के प्रति साझा संकल्प को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में हमारा सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्राजील में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की सह-अध्यक्षता करने के ब्राजील के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति दा सिल्वा को बधाई देता हूं। राष्ट्रपति दा सिल्वा और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए मोदी ने कहा कि वह पिछले साल अपनी ब्राजील यात्रा के दौरान मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की दिल से सराहना करते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दा सिल्वा के नेतृत्व को बेहद अहम बताया। हैदराबाद हाउस में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत और ब्राजील के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप ने लागू किये 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके व्यापक टैरिफकार्यक्रम के बड़े हिस्से को खारिज किए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत दुनिया भर से होने वाले आयात पर 10 प्रतिशत वैश्विक शुल्क लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने श्री ट्रंप के पहले के व्यापक टैरिफ कार्यक्रम को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) राष्ट्रपति को ऐसे व्यापक आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता और यह अधिकार कांग्रेस के पास है। नये टैरिफ व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 122 के तहत लगाये गये हैं और ये लगभग तुरंत प्रभावी होंगे। ये अधिकतम 150 दिनों तक लागू रहेंगे। यह कदम श्री ट्रंप के संरक्षणवादी व्यापार एजेंडे का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भुगतान संतुलन घाटे और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटना है। श्री ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को बेहद निराशाजनक करार देते हुए कहा कि उनके पहले के टैरिफके खिलाफ मतदान करने वाले न्यायाधीशों को शर्म आनी चाहिए। छह-तीन के बहुमत वाले इस फैसले से आईईईपीए के तहत पहले लगाये गये अरबों डॉलर के टैरिफ अमान्य हो गये हैं, जिससे सरकार को 130 अरब से 175 अरब डॉलर तक की राशि वापस करनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत शुल्क समायोजन प्रक्रिया की शुरुआत है और अदालत द्वारा रद्द किये गये टैरिफ के स्थान पर वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ (धारा 232) और व्यापार उपचार उपाय (धारा 301) पहले की तरह लागू रहेंगे।

कांग्रेस आंदोलन पर इंडी गठबंधन में दरार? सपा-बसपा ने की निंदा

नईदिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बिना शर्ट पहने घुस जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना हुई। वीडियो में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को भारत मंडपम के अंदर शर्ट हाथ में लिए हुए नारे लगाते हुए देखा गया। इस कृत्य की निंदा न केवल केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने की, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी की, जिनमें से कई ने वैश्विक मंचों पर राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता पर बल दिया।

एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के विरोध पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बीच आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने जो किया वह उचित नहीं था। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे विदेशी प्रतिनिधियों और विश्व प्रतिनिधियों के सामने हमारे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़े। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी ङ्क पर लिखा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दुनिया के सामने एकजुटता दिखाना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने लिखा कि कल एआई शिखर सम्मेलन में युवा कांग्रेस ने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है! किसी को भी हमारे देश का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, हमें हमेशा दुनिया के सामने एकजुटता दिखानी चाहिए। हम सबको शर्मिंदा कर दिया। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने शनिवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिन पहले दिल्ली में 'एआई इंपैक्ट समिट' के दौरान ''कमीज उतारकर किए गए विरोध-प्रदर्शन'' को अति-अशोभनीय व निंदनीय करार दिया।

प्रमुख समाचार

आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पहुंचे दून

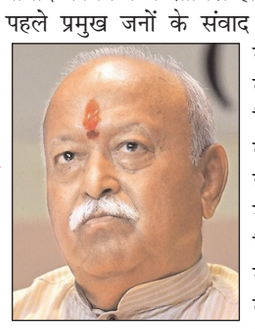

देहरादून। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय प्रवास पर शनिवार की देर शाम देहरादून पहुंच गए। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत दो दिन तक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।डॉ. मोहन भागवत पहले प्रमुख जनों के संवाद में शामिल होंगे जो रविवार को दोपहर दो बजे से नींबूवाला स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में होगा। इसमें गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से विभिन्न संगठनों के प्रमुख लोगों को बुलाया गया है। कार्यक्रम से मंत्री, विधायकों के साथ ही आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी अलग रखा गया है। दूसरे दिन होने वाले संवाद में पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया है। दोनों ही दिन करीब एक-एक हजार लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। शनिवार देर शाम तिलक रोड स्थित जन कल्याण व्यास में डॉ. भागवत पहुंचे। रविवार को सुबह जन कल्याण व्यास में ही रहेंगे। दोपहर से कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मानहानि केसः भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी

मुंबई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि मामले में नई जमानत पेश करने पहुंचे। अदालत ने उनसे नया जमानतदार पेश करने को कहा था, क्योंकि उनके पूर्व जमानतदार और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल दिसंबर में निधन हो गया था। राहुल गांधी इस मामले में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को नए जमानतदार के रूप में पेश कर रहे हैं। उनके वकील नारायण अय्यर के अनुसार, मजिस्ट्रेट ने औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। अय्यर ने कहा कि मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार देशभर में सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा रहा है।वकील ने यह भी कहा कि बचाव पक्ष उचित समय पर अपने गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करेगा। उन्होंने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद है।

डोनाल्ड ट्रंप के हर मूव का कर रहे अध्ययनः गोयल

नईदिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय सरकार अमेरिकी टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द करने के बाद आई है। 6-3 के विभाजित फैसले में, अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प कांग्रेस की मंजूरी के बिना आईईईपीए 1974 के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले पर ध्यान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे।

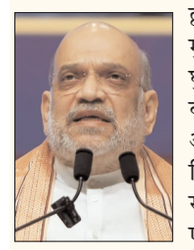

कांग्रेस के पाप से बदली जनसांख्यिकी, हम मुक्त कराएंगे : अमित शाह

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर अवैध घुसपैठ की अनुमति देने का आरोप लगाया, जिससे कथित तौर पर असम की जनसांख्यिकी में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा असम को पिछली सरकार द्वारा किए गए इस पाप से मुक्त कराएगी। उन्होंने घुसपैठियों से प्रभावित धुबरी, बारपेटा, मोरीगांव, नागांव और गोलपारा जैसे जिलों के लिए पार्टी की जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। काम रूप में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान घुसपैठिए यहां घुस आए, जिससे असम की जनसांख्यिकी संकट के स्तर पर पहुंच गई। तब भी हमने घुसपैठ का विरोध किया था। हम असम आंदोलन के समर्थन में पूरे देश से आए थे... लेकिन कांग्रेसी अपनी नींद से नहीं जागे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, धुबरी, बारपेटा, मोरीगांव, नागांव और गोलपारा जैसे जिले मुस्लिम बहुल और घुसपैठियों से प्रभावित क्यों हो गए हैं? भाजपा ही वह पार्टी है जो असम को आपके द्वारा किए गए इस पाप से मुक्त कराएगी।

शंकराचार्य के खिलाफ पास्को एक्ट में एफआईआर

प्रयागराज । इलाहाबाद की सेशन कोर्ट ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पोक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने संबंधित पुलिस थाने को शिकायत पर विधिक प्रावधानों के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जाँच करने को कहा है। यह आदेश शिकायत की सुनवाई के बाद दिया गया है . जिसमें आरोप लगाया गया था. शंकराचार्य ने कथित रूप से नाबालिकों के साथ अवांछित कृत्य किया गया है. शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है. उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है. आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं. वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि शिकायतकर्ता द्वारा दो शपथपत्रों में विरोधाभास है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया, शिकायतकर्ता शामली पुलिस थाना क्षेत्र का कथित हिस्ट्रीशीटर है. उन्हें लखनऊ जाने से रोकने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है। जिसका वह सामना करेंगे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदालत के आदेश पर मामले की जांच शुरू की जाएगी। अधिकारियों का कहना है।

राहुल की राजनीति और सत्ता पक्ष की रणनीति

विजय विद्रोही

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के एक बयान से भारतीय राजनीति में नया उबाल आ गया है। रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे खतरनाक इंसान हैं। अब आप चाहें तो इसे एक सामान्य किस्म का सियासी बयान कह कर हाशिए पर डाल सकते हैं या चूंकि यह संसदीय कार्य मंत्री का बयान है, इसलिए इसके महत्व पर बहस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि संसदीय कार्य मंत्री का काम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद, सामंजस्य बैठाने का होता है ताकि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में यह बयान तो विपक्ष खासतौर से कांग्रेस को उकसाने वाला है।

तो सवाल उठता है कि आखिर बयान क्यों दिया गया, क्या अपनी तरफ से दिया गया या दिलवाया गया? क्या इसके पीछे मोदी सरकार की कोई रणनीति काम कर रही है? क्या यह राहुल गांधी को फिर से घेरने की किसी योजना का हिस्सा है? दिलचस्प है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लगभग ऐसे ही आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ ठोस प्रस्ताव संसद में रख चुके हैं। उधर कांग्रेस की पहल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा जा चुका है। तो क्या राहुल गांधी पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें और बदले में दुबे का प्रस्ताव वापिस ले लिया जाएगा?

रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नक्सलियों, खालिस्तानियों और इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं से संबंध हैं। वह भारत विरोधी विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। वह सोरेस से पैसा लेते हैं। विदेश जाकर देश विरोधी ताकतों से मेल-मुलाकात करते हैं। अब पहली नजर में तो ये गंभीर आरोप हैं। उस नेता विपक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जो 22 सालों से सांसद है। अब कायदे से तो यह माना जाना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री हवा में तलवारबाजी नहीं ही कर रहे होंगे। सबूत होंगे। सबूत हैं तो किसी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई? सबूत सही पाए जाने पर राहुल गांधी जेल की सीखचों के पीछे हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इससे साफ है कि मामला सियासी है। दरअसल

भाजपा खुद तो सत्ता में रहना चाहती है लेकिन साथ ही विपक्ष की स्पेस (जगह) भी अपने पास ही रखना चाहती है। लेकिन जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं और कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंची है, तब से उन्होंने विपक्ष के स्पेस को कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। यह बात साफ है कि केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाले एन.डी.ए. को सिर्फ कांग्रेस की अगुवाई वाला 'इंडिया' गठबंधन ही हटा सकता है। यहां सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी ही नजर आते हैं।

राहुल गांधी ने पहले जातीय जनगणना, फिर संविधान बदलने का आरोप और आरक्षण का मुद्दा उठाकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हैं। अब वह कभी जनरल नरवणे की पांडुलिपि का जिक्र करते हैं तो कभी ट्रम्प के साथ हुई डील का सवाल उठाते हैं। कभी एपस्टीन फाइल्स का हवाला देते हैं तो कभी ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी अमरीका से होने वाली डील पर 5 सवाल पूछ रहे हैं। उधर अमित शाह, पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान उन्हें झूठा बता रहे हैं, गिरिराज सिंह नेहरू-एडविना की तस्वीरें लहरा रहे हैं, निशिकांत दुबे राहुल गांधी को चुनाव लडने से रोकने का प्रस्ताव ला रहे हैं और किरण रिजिजू सबसे खतरनाक इंसान बता रहे हैं। हो सकता है कि भाजपा को लगता हो कि नैरेटिव इस तरह बदला जा सकता है, एपस्टीन फाइल्स से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता है और विपक्ष के आरोपों पर लंबी लकीर खींची जा सकती है।हकीकत तो यही है कि देश में आमतौर पर शायद ही कोई मानेगा कि विपक्ष का नेता देशद्रोही हो सकता है। राहुल गांधी कई बार शब्दों का उचित चयन नहीं कर पाते, वह ड्क्षहदी में जब भी भाषण देते हैं तो इधर-उधर सही शब्द के मामले में लडखड़ा जाते हैं, उनके भाषण का कंटैंट मजबूत होता है लेकिन वह संवाद स्थापित नहीं कर पाते, जनता तो छोड़िए, अपने कार्यकर्त्ताओं तक ठीक से पहुंच नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी के नेता भी दबी जुबान से मानते हैं कि राहुल गांधी कभी-कभी किसी मुद्दे को जबरन घसीटते रहते हैं, जबकि हर मुद्दे की एक एक्सपायरी डेट होती है।

अक्सर कहा जाता है कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के साथ उस अदावत से पेश नहीं आते, जैसे कि राहुल गांधी आते हैं। बात सही है लेकिन राज्यों के नेता अपने राज्य तक सीमित रहते हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री तो कांग्रेस से ही होगा। राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और विपक्षी दलों के क्षत्रपों के बीच अदावत चरम पर होती है।

नक्सलवाद की प्रतीकों पर वार, सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली में 44 नक्सली स्मारक ध्वस्त

जगदलपुर। नक्सलवाद की जड़ों पर निर्णायक प्रहार करते हुए छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त अभियान में सी-60, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस ने मिलकर नक्सलियों से जुड़े 44 स्मारकों को ध्वस्त किया। ये स्मारक वर्षों से नक्सली प्रभाव और प्रचार के प्रतीक माने जा रहे थे।

कार्रवाई का उद्देश्य नक्सलवाद के महिमामंडन पर रोक लगाना और स्थानीय युवाओं को गुमराह होने से बचाना है। अधिकारियों के मुताबिक अभियान पूरी तरह योजनाबद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा आकलन के बाद अंजाम दिया गया। बलों की इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का संदेश और प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में नक्सल विरोधी अभियान लगातार तेज किए जा रहे हैं, ताकि शांति और विकास का रास्ता साफ हो सके।

मनेन्द्रगढ़ शासकीय सिविल अस्पताल के दावों पर सवाल, बुनियादी सुविधाओं समेत डॉक्टरों का टोटा

■ मनेंद्रगढ़ का शासकीय सिविल अस्पताल सिर्फ कागजों में शत प्रतिशत सुविधाओं के साथ संचालित हो रहा है. अस्पताल की हकीकत कुछ और ही है.

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) को उन्नत कर 220 बिस्तरीय सिविल अस्पताल बनाए जाने के दावों के बीच अब व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कागज में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन अस्पताल पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों का अनुभव कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने 220 बिस्तरों के संचालन का दावा किया है, लेकिन पूरी क्षमता से सेवाएं अब तक शुरू नहीं हो सकी हैं। अतिरिक्त भवन, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनपद कार्यालय के भवनों का अस्थायी उपयोग कर वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या बिना पर्याप्त स्थायी आधारभूत संरचना और संसाधनों के इतनी बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं अभी भी संक्रमण काल में हैं और मरीजों को अपेक्षित सुविधाएं पूरी तरह नहीं मिल पा रही हैं।अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने सबसे गंभीर समस्या पानी की बताई है। ग्रामीण महिला सोनमति ने भी शौचालय और पीने के पानी की समस्या के बारे में बताया है। सोनमति के मुताबिक टाइम से पानी नहीं मिलता। नल बहुत दूर है, वहां जाकर पानी लाना पड़ता है। वहीं अस्पताल में 15 विशेषज्ञ और 10 से अधिक एमबीबीएस डॉक्टरों की पदस्थापना का दावा किया जा रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर विशेषज्ञ सेवाओं की नियमित उपलब्धता को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। सबसे अधिक चिंता स्त्री रोग विभाग को लेकर सामने आ रही है, जहां वर्तमान में केवल एक ही स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं। उनके अवकाश या अनुपस्थिति की स्थिति में गर्भवती महिलाओं को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में मरीजों को जिला अस्पताल या बड़े शहरों की ओर रेफर किया जाता है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज के दावे कमजोर पड़ते नजर आते हैं। अस्पताल प्रशासन 24 घंटे इमरजेंसी सेवा संचालित होने की बात कह रहा है। लेकिन गंभीर दुर्घटना या जटिल मामलों में आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञों की तत्काल उपलब्धता को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जटिल सर्जरी और गंभीर चिकित्सा मामलों में अब भी बड़े शहरों पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर सुविधाओं के विस्तार की प्रक्रिया जारी होने की बात कही जा रही है। वहीं सीएमएचओ डॉ। अविनाश खरे ने एक और स्त्री रोग विशेषज्ञ के संभावित ज्वाइन करने की जानकारी दी है। अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। संसाधनों और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। जल्द ही 220 बिस्तरों की पूरी क्षमता के साथ अस्पताल संचालित होगा।

पर्यटन स्थल में भीषण आग से मचा हड़कंप

सरगुजा। मैनपाट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट में बीते शुक्रवार की देर रात भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। आग ने देखते ही देखते आसपास बनी झोपड़ीनुमा दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में अधिकांश दुकानें जलकर राख हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और तत्काल प्रशासन को सूचना दी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारणों का अब तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुकानें जलती हुई दिख रही हैं। गौरतलब है कि इस आगजनी की घटना से छोटे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से सहायता और मुआवजे की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में जांच शुरू कर दी गई है।

दो दिनों बाद मिला लुटेरों का रिमांड

चारों लुटेरों को लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचेगी पुलिस टीम

बिलासपुर। बिलासपुर में सराफा व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर लूट के मामले में यूपी पुलिस ने भी एफआईआर कायम की है, जिसकी वजह से उन्हें छत्तीसगढ़ लाने के लिए प्रोडक्शन रिमांड की जरूरत पड़ी। दो दिनों तक बिलासपुर की पुलिस टीम आरोपियों के रिमांड के लिए जूझती रही। शुक्रवार शाम को मिर्जापुर की कोर्ट से चारों आरोपियों का रिमांड मिल गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपियों को लेकर बिलासपुर आने के लिए निकल गई है। आज शनिवार देर शाम या रात तक पुलिस टीम चारों आरोपियों को लेकर बिलासपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद उन्हें यहां भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा सकती है। आरोपियों से पूछताछ में कई नए तथ्य मिलने की संभावना है। राजकिशोर नगर में सराफा कारोबारी से लूट करने वाले चार आरोपी मिर्जापुर के अहरौर में पकड़े गए थे। पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में विजय लांबा और मोनू उर्फ राहुल के पैर में गोली लगी थी। शॉर्ट एनकाउंटर के कारण मिर्जापुर पुलिस ने लूट का माल रखने, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया था। प्रोडक्शन रिमांड लेने में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सीएसपी निमितेश सिंह अपनी टीम के साथ आरोपियों का पीछा करते यूपी गए हैं। वे लगातार यूपी पुलिस और बिलासपुर पुलिस से संपर्क कर समन्वय बना रहे हैं। वहां से जरूरी कागजात मंगवाने पर बिलासपुर से सभी दस्तावेज और विवेचक मिर्जापुर के लिए रवाना किए गए। इसके बाद शुक्रवार शाम तक सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद अदालत से आरोपियों की रिमांड मिल सकी। टीम शनिवार शाम तक आरोपियों को बिलासपुर ले आएगी। घटना की सूचना मिलते ही कुछ ही देर में आईजी रामगोपाल गर्ग खुद ही मौके पर पहुंच गए। उनके साथ एडिशनल एसपी मधुलिका सिंह,पंकज पटेल, सीएसपी निमितेश सिंह, टीआई प्रदीप आर्या भी मौके पर पहुंचे।

स्टेट हाईवे बाधित कर मना रहे थे बर्थडे, पुलिस ने सात आरोपियों को दबोचा

सूरजपुर। जिले के अम्बिकापुर-बनारस मार्ग पर सोनवाही आरव रेस्टोरेंट के सामने बीते 16 फरवरी के रात्रि करीब 10-11 बजे अमितेश गुप्ता, अंशुल अग्रवाल व उसके 4-5 अन्य साथियों के द्वारा लोक मार्ग में वाहन खड़ी कर यातायात बाधित कर बर्थडे बनाते हुए आतिशबाजी किया गया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर की तरफ से आरोपियों की पतासाजी कर धरपकड़ के लिए पुलिस की 2 टीमे गठित कर लगाया है। जिसके बाद से ही पुलिस की टीमे लगातार आरोपियों के मिलने के संभावित स्थानों पर दबिश देने में लगी हुई थी। इसी बीच प्राप्त सूचना व तकनीकी मदद से पुलिस टीमों ने कई स्थानों पर दबिश देकर आरोपी अमितेश गुप्ता उर्फ जानू पिता राकेश गुप्ता उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 44 अम्बिकापुर, अंशुल अग्रवाल पिता सोहन लाल अग्रवाल उम्र 25 वर्ष निवासी अम्बिकापुर, प्रथम अग्रवाल पिता प्रमोद अग्रवाल उम्र 24 वर्ष निवासी मणीपुर अम्बिकापुर, शुभम अग्रवाल पिता सुभाष अग्रवाल उम्र 23 वर्ष निवासी कुण्डला सिटी अम्बिकापुर, महेश साहू पिता विनय साहू उम्र 27 वर्ष निवासी बिलासपुर चौक अम्बिकापुर, निखिल रामा पिता तुलसी राम उम्र 26 वर्ष निवासी जनपदपारा अम्बिकापुर व अरूण देवांगन पिता कैलाश प्रसाद देवांगन उम्र 39 वर्ष निवासी लटोरी, चौकी लटोरी को पकड़ा गया।

सक्ती टोल प्लाजा पर कलेक्टर के निरीक्षण में मिली भारी गड़बड़ियां

सक्ती। सक्ती टोल प्लाजा फिर विवादों के घेरे में आ गया है। टोल संचालक पर अवैध वसूली और वाहन मालिकों से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत कलेक्टर से हुई, जिसके बाद सक्ती कलेक्टर अचानक टोल प्लाजा जांच में पहुंच गए। मौके पर गड़बड़ियां देखकर कलेक्टर ने टोल प्लाजा संचालक को फटकार लगाई।

मामले में कलेक्टर का कहना है कि निरीक्षण में गड़बड़ियां मिली हैं और शिकायत सही पाई गई है। कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया जा रहा है। मामले में टोल

मैनेजर ने दिया गैर-जिम्मेदाराना बयान

प्लाजा के मैनेजर का भी गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। मैनेजर का कहना है कि हमें केवल वसूली की जिम्मेदारी मिली है, सुविधा देने की नहीं। जबकि एनएचएआई के गाइडलाइन में टोल प्लाजा में पीने का पानी, शौचालय, एम्बुलेंस, टो वाहन सहित कई अन्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

मगर सक्ती के टोल प्लाजा के मैनेजर के बयान ने एनएचएआई के नियमों पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि, सक्ती कलेक्टर ने पूरे मामले में एनएचएआई को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की बात कही है।

टोल टैक्स छूट के संबंध में जब उनसे पूछा गया तो हैरान करने वाला जवाब सामने आया। मैनेजर जयंत पांडे का कहना है कि कुछ राजनीतिक लोगों को भी छूट देते हैं, जो इस दायरे में नहीं आते और जो नियम के खिलाफ है।

फिर भी करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर शासन को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने खुद के नियम बनाए हुए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

अजीबोगरीब चोरी, पिता की शिकायत पर बेटा गिरफ्तार

सूरजपुर। विश्रामपुर पुलिस के पास एक पिता पहुंचा और अपने बेटे की शिकायत की। पिता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे ने घर में चोरी की है। बेटे के खिलाफ पिता की रिपोर्ट पुलिस ने तो दर्ज कर ली लेकिन वो भी हैरान थी। लिहाजा पूरे मामले की जांच शुरू की। कुमदा बस्ती निवासी रामविलास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटे दिगंबर ने अपने साथी मुन्ना पैकरा के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की। पिता ने आरोप लगाया कि बेटे ने पहले घर का ताला तोड़ा और घर में रखा तीन क्विंटल धान चोरी कर लिया। पिता की शिकायत पर विश्रामपुर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस जांच में घर से चोरी की पुष्टि हुई। जांच में ये भी पता चला कि आरोपियों ने जयनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल भी चोरी की थी। उसी चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर वे अपने घर पहुंचे और लगभग 3 क्विंटल धान चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की।

तीन लुटेरों ने सराफा कारोबारी से की उठाई गिरी

बिलासपुर। बिलासपुर में सराफा व्यापारियों से लूट की वारदातें रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार सराफा व्यापारी को लूटने की घटना हुई है। राजकिशोर नगर सराफा व्यापारी से लूट के बाद अब दूसरी घटना सीपत थाना क्षेत्र में हुई है।सीपत चौक के सराफा व्यापारी से करीब 10 किलो चांदी और 100 ग्राम सोने के जेवर से भरे थैले को 3 नकाबपोश युवक छीनकर बाइक से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जिले में नाकेबंदी कर बाइक सवार युवकों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक जांजगीर जिला बलौदा निवासी विनय सोनी की सीपत खमरिया में ज्वेलर्स दुकान का संचालक है। वो प्रतिदिन रात में दुकान बंद करके कीमती सोने चांदी के जेवर अपने साथ घर ले जाते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे दुकान में रखे 10 किलो चांदी के आभूषण और 100 ग्राम सोने की आभूषण थैले में रखकर वो दुकान का शटर बंद कर रहे थे।इसी बीच तीन नकाबपोश बाइक सवार उनके पास पहुंचे और सोने चांदी से भरा बैग उठाकर फरार हो गए।

अनिरुद्ध नीरव ने सरगुजिहा को बनाया उत्कृष्ट साहित्य

सरगुजा। हमारे देश की मात्रभाषा तो हिन्दी है लेकिन पूरे देश में ना जाने कितनी स्थानीय बोली और भाषायें हैं। जिनमे वहां रहने वाले लोग बातचीत और लेखन का काम करते हैं। हर क्षेत्र अपनी रीजनल लैंग्वेज पर गर्व करता है और उसके उत्थान का प्रयास वहां रहने वाले साहित्यकारों के जिम्मे होता है। छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानीय बोली है जिनमें से एक है सरगुजिहा। इस बोली को बोलचाल की भाषा में तो प्रयोग किया जाता लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में भी सरगुजिहा को भी स्थान दिया। उस दौर के महान साहित्यकार अनिरुद्ध नीरव ने सरगुजिहा लेखन पर इतना गहरा काम किया कि इसे एक विशेष पहचान दिलाई। नीरव के नव गीतों में पूरा सरगुजा बसता है। महज उनके गीतों को सुनकर आप पूरे सरगुजा भ्रमण की कल्पना कर सकते हैं। उनकी रचनाओं में सरगुजा की प्रकृति का समावेश दिखता है। साहित्यकार मानते हैं कि नीरव अपनी रचनाओं में उपमा यानी तुलना का जो स्तर रखते थे वो बड़ा ही आनंददायक है।

अबूझमाड़ का हर्बल गुलाल शहर में बिखेरेगा रंग

नारायणपुर। होली में केमिकल वाले रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं।कई बार केमिकल युक्त रंगों से लोग बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में केमिकल रंगों के दुष्प्रभाव को देखते हुए अबूझमाड़ की महिलाओं ने नैचुरल कलर बनाया है। कृषि विज्ञान केन्द्र नारायणपुर में महिला स्वयं सहायता समूह ने मेहनत से हर्बल गुलाल बनाया है।जो साल दर साल लोगों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। महिलाओं के हाथों से बनाया गया ये गुलाल अब वनांचल से निकलकर रायपुर बिलासपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंच रहा है।

महिला समूह की सदस्य बताती हैं कि कुछ साल पहले होली में बाजार के गुलाल से उनके परिवार और गांव के कई लोगों को आंखों में जलन, त्वचा में खुजली और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हुईं। इस घटना ने महिलाओं को रंगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। समाधान की तलाश में महिलाएं कृषि विज्ञान केंद्र नारायणपुर पहुंचीं, जहां उनकी मुलाकात प्रमुख वैज्ञानिक देवेंदु दास से हुई।

स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूलों में कराएगा 5वीं-8वीं की परीक्षा

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा करने का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग को दिया है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में संचालित सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त लगभग 6200 निजी हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश को प्रदेश में बिना मान्यता या संदिग्ध तरीके से संचालित फर्जी सीबीएसई स्कूलों के लिए करारा झटका माना जा रहा है। लंबे समय से ऐसे स्कूल खुद को सीबीएसई से जुड़ा बताकर एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन न तो उनके पास वैध मान्यता थी और न ही शासन की अनुमति।

कोरबा में अवैध रेत पर शिकंजा

■ एसडीएम के निर्देश पर तीन ट्रैक्टर जब्त, कटघोरा में बड़ी कार्रवाई

कोरबा। जिले में एसडीएम तन्मय खन्ना के निर्देश पर तहसील प्रशासन ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे तीन ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जिन्हें थाना कटघोरा में सुपुर्द किया गया है। प्रशासन की यह कार्रवाई कटघोरा तहसील क्षेत्र में लगातार बढ़ते अवैध उत्खनन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से की गई है। एसडीएम के निर्देशन में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर अवैध रेत खनन और परिवहन में संलग्न वाहनों पर त्वरित कार्रवाई की।एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि अवैध रेत उत्खनन से न केवल राजस्व की हानि होती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जिले में अवैध गतिविधियों पर

रोक लगाने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर और भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुदूर गांवों में पहुंचे विधायक विक्रम मंडावी

बीजापुर। बीजापुर के सुदूर पामेड़ क्षेत्र में विधायक विक्रम मंडावी ने गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। राजस्व पट्टा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और राशन व्यवस्था जैसी समस्याएं उठीं। छत्तीसगढ़ के सबसे सुदूर और उपेक्षित अंचलों में से एक बीजापुर जिले के पामेड़ क्षेत्र में बीते गुरुवार और शुक्रवार को एक असाधारण दृश्य देखने को मिला। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी जब छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा से सटे इन दुर्गम गांवों में पहुंचे, तो ग्रामीणों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। फूल-मालाओं और जयकारों के बीच हुआ उनका स्वागत यह बता रहा था कि यहां के लोग लंबे

समय से किसी जनप्रतिनिधि की प्रतीक्षा में थे। पामेड़ क्षेत्र, जहां छत्तीसगढ़ की सीमा तेलंगाना से मिलती है, आदिवासी बहुल, नक्सल प्रभावित और विकास की दृष्टि से सर्वाधिक वंचित इलाकों में गिना जाता है। यहां के गांव आज भी बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। इन गांवों में विधायक मंडावी का यह दौरा महज एक राजनीतिक भ्रमण नहीं, बल्कि जनसंवाद बन गया।

सरकारी नौकरी का झांसा देकर 25 लाख की ठगी

■ फिर पीड़ितों पर दबाव बनाने आरोपी ने परिजनों से करवाया गुमशुदगी दर्ज

बिलासपुर। सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला क्षेत्र निवासी युवक ने ग्रामीण के बेटे और भतीजे को नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 25 लाख रुपये की ठगी कर लिया। इसके बाद आरोपी गायब हो गया।

फिर पीड़ितों पर दबाव बनाने के लिए आरोपी ने उल्टा अपने परिजनों के माध्यम से थाने में गुमशुदगी दर्ज करवा दी। मामले में

बिलासपुर जिले की हिर्री पुलिस ने अदालत के आदेश पर जुर्म दर्ज कर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जानकारी के अनुसार, जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम उरैहा निवासी एवं पोल्ट्री फार्म संचालक अंबिका प्रसाद भारद्वाज ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान मुलमुला क्षेत्र के ग्राम छेड़ोलिया में रहने वाले राजा भैया लहरे (26) से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री अमरजीत भगत के करीबी अधिकारियों तक पहुंच का दावा किया। साथ ही उसने परिवार न्यायालय रायपुर एवं मुंगेली में सरकारी नौकरी लगवा देने की बात भी कही। आरोपी ने विश्वास जीतने के लिए अंबिका प्रसाद की मुलाकात रायपुर स्थित सरगुजा कुटीर में एक व्यक्ति से भी कराई थी। आरोपी की बातों में आकर अंबिका प्रसाद ने अपने बेटे और भतीजे की नौकरी लगवाने के लिए 17 लाख 65 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जबकि 7 लाख 35 हजार रुपये नकद दिए। इसके बावजूद उनके बेटे और भतीजे की नौकरी नहीं लगी। जब उन्होंने अन्य लोगों से पूछताछ की तो ठगी का पता चला।

संक्षिप्त समाचार

मोदी व शाह ने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री साय को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली-रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की प्रगति को गति देने के उनके प्रयास सराहनीय हैं और लोगों के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ रहा है। उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए जवाब दिया, आपके नेतृत्व और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र ने ही छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार को जनकल्याण की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में विकसित भारत 2047 के महायज्ञ में छत्तीसगढ़ अपनी पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ समर्पित रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शांति, सुरक्षा और हर वर्ग के कल्याण का सुंदर कालखंड देख रहा है। मां दंतेश्वरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं।

खेल के मैदान से मिलता है स्वास्थ्य, समन्वय और सफलता का मंत्र : साव

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा

कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर प्रेस क्लब द्वारा सुभाष स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय कुलदीप निगम स्मृति इंटर-प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पहुंचकर पत्रकार खिलाड़ियों से आत्मीय मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेल मड़ई के सफल आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब और पत्रकारों को बधाई दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री साव ने फाइनल मैच खेल रही संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक टीम के कप्तान एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री मोहन तिवारी तथा विस्तार न्यूज टीम के कप्तान श्री मृगेंद्र पांडेय सहित दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक टीम ने विस्तार न्यूज को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सुभाष स्टेडियम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल का मैदान व्यक्ति को जीवन की अनमोल पूंजी प्रदान करता है। खेल हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छे दोस्त देता है, समन्वय की भावना सिखाता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति को यह सब मिलता है तो वह जीवन में प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है और निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर होता है। श्री साव ने रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पिछले कई दिनों से आयोजित इस खेल मड़ई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी स्नेह को बढ़ाते हैं और स्वस्थ जीवन-शैली के लिए प्रेरित करते हैं। पत्रकारिता जैसे दायित्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय साथियों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार साथी इसी तरह मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करते रहें।

खारुन पर बनेगा हाई-लेवल ब्रिज 16.36 करोड़ की मंजूरी

रायपुर। राजधानी क्षेत्र में यातायात दबाव कम करने और ग्रामीण-शहरी संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने खारुन नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच मार्ग निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्य जिला मार्ग उरला-पठारीडीह-बेरला पर बनने वाली इस परियोजना के लिए 16 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार स्वीकृति के बाद निर्माण प्रक्रिया तेज की जाएगी। निविदा प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण गुणवत्ता को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। यह पुल विशेष रूप से बारिश के मौसम में राहत देगा। खारुन नदी का जलस्तर बढ़ने पर इस मार्ग से आवागमन प्रभावित हो जाता है, जिससे लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता लेना पड़ता है। नए हाई-लेवल ब्रिज के बनने से वर्षभर निर्बाध आवाजाही संभव होगी। यातायात सर्वे के अनुसार इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, खासकर शाम के समय। नया पुल शुरू होने के बाद वाहनों का दबाव विभाजित होगा, जिससे जाम की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी ने पुल की रूपरेखा आगामी वर्षों की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की है। आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी और आवासीय विस्तार को देखते हुए इसे दीर्घकालिक समाधान के रूप में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने पर राजधानी और आसपास के ग्रामीण इलाकों को बेहतर और सुरक्षित सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा।

विधानसभा के बजट सत्र में 15 बैठकें प्रस्तावित

विस अध्यक्ष रमन सिंह बोले- दो महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश, 24 फरवरी को पेश होगा बजट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में सत्र की रूपरेखा और कार्यसूची की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बजट सत्र में कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं। सत्र की शुरुआत सोमवार, 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:05 बजे राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा 25 फरवरी को की जाएगी। अभिभाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी 24 फरवरी 2026 को अपराह्न 12:30 बजे वर्ष 2026-27 का आय-व्ययक (बजट) प्रस्तुत करेंगे। बजट भाषण का सीधा प्रसारण दूरदर्शन रायपुर और आकाशवाणी रायपुर से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर सामान्य चर्चा 26 और 27 फरवरी को होगी। इसके बाद 9 से 17 मार्च तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा निर्धारित है। 17 मार्च को आय-व्ययक की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जाएगा, जबकि 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर चर्चा और पारण की तिथि तय की गई है।

दो महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तावित

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि शासकीय विधि-विषयक कार्यों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण विधेयकों की

सूचनाएं प्राप्त हुई हैं—

(1) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026

(2) छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक, 2026

इन विधेयकों को लेकर सत्र के दौरान राजनीतिक चर्चा और बहस की संभावना जताई जा रही है।

सत्र के लिए अब तक कुल 2813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 1376 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 61 सूचनाएं, नियम 139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, 13 अशासकीय संकल्प, शून्यकाल की 9 सूचनाएं तथा 112 याचिकाएं भी प्राप्त हुई हैं।

सत्र के दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य दीनदयाल सिंह पोर्ते के निधन का उल्लेख भी किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बजट सत्र में वित्तीय, विधायी और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विषयों पर सार्थक बहस की संभावना है, जिससे राज्य की नीतिगत दिशा तय होगी।

कवासी लखमा बजट सत्र में होंगे शामिल

पूर्व मंत्री कवासी लखमा छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सत्र में उनकी उपस्थिति की अनुमति कुछ शर्तों के आधार पर दी है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी, 24 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और 25 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी।

साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जानकारी दी की शराब घोटाले मामले में एक साल बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा की शर्तों के आधार पर कवासी लखमा बजट सत्र में हिस्सा लेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा 3 फरवरी को कवासी को अंतरिम जमानत का लाभ दिया गया। जांच के दौरान याचिकाकर्ता के संबंध में उचित फैसला किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कवासी लखमा को 7 फरवरी को अभिमत मांगा गया और 2026 में अभिमत व्यक्त किया गया। कवासी लखमा को निम्न शर्तों के आधार पर भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

कवासी लखमा को निम्न शर्तों के आधार पर भाग लेने की प्रदान की गई अनुमति-

- आने और जाने की जानकारी विधानसभा सचिव को देनी होगी।
- वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे। कड़ाई से अपनी नो स्पीच का पालन करेंगे।
- उनकी उपस्थिति केवल सत्र में ही रहेगी। यदि उन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया, तो उनकी अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।
- बजट सत्र के अन्य विषयों की चर्चा में वे भाग ले सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर चल रहे केस के संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे।
- सदस्यों को इसकी जानकारी है और यह मामला न्यायालय में होने के कारण कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आ सकता है धर्मांतरण विधेयक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संकेत दिया है कि इसे आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश होना है और उसकी सभी तैयारियां जारी हैं। धर्मांतरण संबंधी विधेयक पर भी चर्चा चल रही है और संभव है कि यह सत्र में लाया जाए।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और समय आने पर निर्णय लिया जाएगा।

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए शर्टलेस प्रदर्शन पर भी विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे शर्टलेस नहीं, सेमलेस प्रदर्शन करार देते हुए कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि यदि किसी को किसी प्रक्रिया में त्रुटि लगती है तो संबंधित मंत्री का घेराव करना समझ में आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में, जहां अनेक देशों के प्रतिनिधि मौजूद हों, इस तरह का प्रदर्शन करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आयोजन में एक संस्था द्वारा गड़बड़ी किए जाने पर उसे अलग कर दिया गया था, उसके बाद मेहमानों के सामने इस प्रकार का व्यवहार शर्मनाक है। उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि हर मंच को राजनीति का माध्यम बनाना उचित नहीं है।

एसआईआर के अंतिम प्रकाशन को लेकर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंतिम प्रकाशन का दिन है। उनके अनुसार मतदाता सूची में समय-समय पर पाई जाने वाली गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक थी।

उन्होंने कहा कि कई ऐसे नाम मतदाता सूची में दर्ज थे जो अब संबंधित स्थान पर नहीं रह रहे हैं। यदि कोई घुसपैठिया है तो उसका नाम सूची से हटना ही चाहिए। सरकार का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है।

मुख्यमंत्री साय ने जन्मदिन पर किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने 62वें जन्मदिन के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की तथा रक्तदाताओं को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री के 62वें जन्मदिन के अवसर पर अल्फा ग्लोब फाउंडेशन, रायपुर तथा शिवनाथ ब्लड सेंटर द्वारा 62 लोगों के रक्तदान की विशेष व्यवस्था की गई थी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान महादान है और यह मानवता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं, प्रसव एवं गंभीर बीमारियों के दौरान जब मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में रक्तदान मरीजों के जीवन में नई आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए हैं, जिससे आवश्यकता पडने पर वे या उनके परिजन निःशुल्क रक्त प्राप्त कर सकेंगे।उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा एक वर्ष में लगभग 11 हजार यूनिट रक्त संग्रह का संकल्प लिया गया है तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न ब्लड बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस अवसर पर सुरक्षित यातायात जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान करने तथा सड़क यातायात नियमों का हर समय पालन करते हुए जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने सभी रक्तदाताओं, आयोजकों, चिकित्सक दल एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिविर की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक म्हस्के, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा सहित, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजु एस सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण तथा अल्फा ग्लोब फाउंडेशन, रायपुर की संचालक डॉ. पूनम अग्रवाल, संस्थान के अन्य प्रतिनिधि और रक्तदाता उपस्थित थे

मुख्यमंत्री साय ने बालक आश्रम बगिया में मनाया अपना 62वां जन्मदिवस

- बच्चों को केक और चॉकलेट देकर दी शुभकामनाएं

जशपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना 62वां जन्मदिवस बगिया स्थित बालक आश्रम के बच्चों के बीच मनाकर इस दिन को उनके लिए हमेशा के लिए यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री ने बगिया हेलीपैड के समीप स्थित बालक आश्रम बगिया पहुंचकर बच्चों के साथ केक काटा और उनके साथ आत्मीय समय बिताया। आश्रम के बच्चे मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न नजर आए। वे उत्साहपूर्वक उनके चारों ओर एकत्र हो गए और उनसे बातचीत करने लगे।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्नेहपूर्वक संवाद किया और उनका हालचाल जाना। उनके सहज, सरल और संवेदनशील व्यवहार से बच्चे भावविभोर हो उठे और खुशी से चहकते हुए उनसे बातें करते रहे। इस दौरान आश्रम परिसर में खुशियों और उत्साह का विशेष वातावरण देखने को मिला।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को अपने हाथों से केक और चॉकलेट वितरित कर उन्हें जन्मदिवस की खुशी में सहभागी बनाया। बालक आश्रम बगिया में कक्षा पहली से पांचवीं तक के छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें

अधिकांश बच्चे आदिवासी समुदाय से हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने परिवार, समाज तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी।

इस अवसर पर विधायक गोमती साय, कमिश्नर नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार तथा प्रशिक्षु आईएफएस यशस्वी मौर्य, भरत सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और आश्रम के शिक्षक और अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

62वें जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने 62वें जन्मदिवस के अवसर पर जशपुर जिले के दोकड़ा स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुँचकर भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र एवं बहन सुभद्रा की विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय तथा परिवार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मंदिर परिसर में परिक्रमा कर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया तथा प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की मंगलकामना की। उन्होंने प्रदेश में शांति, खुशहाली और निरंतर प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए कहा कि जनकल्याण ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश के विकास के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया पूरी, अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन

25 लाख वोटरों के नाम कटे, अब प्रदेश में 1,87,30,914 वोटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद राज्य की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी और संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान लगभग 24 लाख 99 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल 1,87,30,914 मतदाता हैं। उन्होंने अभियान में सहयोग देने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है।

पहले और बाद के आंकड़े

एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 थी।

प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1 करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 हो

गई। इसके बाद आपत्तियों और दावों की सुनवाई के उपरांत अंतिम निर्वाचक नामावली जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 हो गई। अंतिम चरण में सुनवाई के बाद 2 लाख 34 हजार 994 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। इस तरह पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी या दोहराव वाले नाम हटाकर सूची को शुद्ध किया गया।

पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव पर जोर

निर्वाचन विभाग का कहना है कि इस अभियान से मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। इससे आगामी चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची के शुद्धिकरण का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और फर्जी नामों पर रोक लगाई जा सके।

मतदाता सूची में नाम नहीं है तो करें ये काम

यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर उसके साथ घोषणा पत्र और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर लगाया भाजपा एजेंट का आरोप

- बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा- कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्था पर नहीं करती विश्वास

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी और संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। एसआईआर अभियान के दौरान लगभग 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं के नाम सूची से

हटाए गए हैं। अब प्रदेश में कुल 1,87,30,914 मतदाता हैं। मतदाता सूची के फाइनल लिस्ट को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को भाजपा एजेंट बनकर काम करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करती है।

एसआईआर में करीब 25 लाख लोगों के नाम काटे जाने पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैदु ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने गुंडागर्दी कर प्रदेश में अत्याचार किया है। बीजेपी ने अधिकारियों के जरिए बड़ी संख्या में वोट काटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की है। निर्वाचन आयोग भाजपा की एजेंट बनकर काम कर रही है।

वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस देश की संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं करती है। वे ऐसे कृत्य करते हैं जैसे उन्हें न्यायालय के निर्णयों पर विश्वास नहीं होता है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि किसी जगह चुनाव में कांग्रेस जीतती है और छत्तीसगढ़ में उनके विधायक जीतकर आते हैं, तो फिर ईवीएम में क्या दोष था?

किरणसिंहदेव ने आगे कहा कि यह प्रजातंत है और जनता ही सर्वोपरि है। ऐसी आलोचना कांग्रेस करती है, उन्हें सरकार में आने की हड़बड़ी है और जनता के बीच उथल-पुथल का वातावरण बनाना चाहती है।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 113/नि.शा./ का.अ./ लो.स्वा.यां./खण्ड, रायपुर, दिनांक 09.02.2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	कार्य का नाम	राशि (रु.लाख में)
1.	रायपुर जिले के विकासखंड तिल्दा के ग्राम कठिया जलप्रदाय योजना के अंतर्गत शिफ्टिंग कार्य हेतु राईजिंग मेन में 90mm dia 10kg/cm2 के UPVC पाईप 800 मीटर, 100 मि.मी. व्यास के जी.आई. पाईप 30 मीटर का प्रदाय कर बिछाने, जोड़ने, परीक्षण कर चालू करने का कार्य।	12.60

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.02.2026 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रायपुर छत्तीसगढ़

जी-252606806/3

द्रमुक-कांग्रेस में अनबन का नियंत्रण हाईकमान ने लिया

राहिल नोरा चोपड़ा

तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कझगम-कांग्रेस गठबंधन के अंदर चल रही अनबन पर कांग्रेस हाईकमान ने पूरी तरह से सीधा कंट्रोल कर लिया है। हालांकि 22 फरवरी से फॉर्मल बातचीत शुरू होने वाली है लेकिन कांग्रेस नेताओं के सार्वजनिक बयानों से पहले ही इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि यह अनबन असली है या सोची-समझी मोलभाव की रणनीति। इसकी शुरुआती चिंगारी कांग्रेस की सीटों के बड़े हिस्से और गठबंधन के सत्ता में लौटने पर शासन में ज्यादा तय भूमिका की मांग लगती है। सांसद मणिकम टैगोर और रणनीतिकार प्रवीण चक्रवर्ती जैसे कांग्रेस नेताओं के मुखर बयानों से यह मुद्दा और बढ़ गया है, जिन्होंने एक्टर-पॉलिटिशियन विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम के साथ जुडने़ की संभावना सहित दूसरे पॉलिटिकल अलायंस के बारे में सार्वजनिक रूप से इशारा किया है। लेकिन हाल ही में, सीनियर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कनिमोझी के जरिए द्रमुक नेतृत्व को साफ-साफ बता दिया है कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी रणनीति पर जोर नहीं देगी जिससे गठबंधन में तनाव पैदा हो, जिसमें पावर-शेयरिंग पर बातचीत भी शामिल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले कोई दूसरा गठबंधन चुनने या विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (टी.वी.के.) के साथ जाने के किसी भी ऑप्शन से मना कर दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि द्रमुक ने एक इनडायरैक्ट अल्टीमेटम दिया है कि कांग्रेस गठबंधन में रह सकती है लेकिन सरकार में हिस्सेदारी के बिना और अगर इससे पावर-शेयरिंग पर कोई जोर पड़ता है, तो वह छोडने़ के लिए आजाद हैं। ऐसे भी सुझाव हैं कि द्रमुक ने गठबंधन को आसानी से जारी रखने के लिए प्रवीण चक्रवर्ती और मणिकम टैगोर जैसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बयानबाजी के बावजूद, दोनों पार्टियां भाजपा विरोधी एकता को एक जोडने़ वाली ताकत के तौर पर जोर दे रही हैं। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के अंदर सत्ता की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि लीडरशिप में बदलाव का फैसला पहले ही हो चुका है और चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया सही समय पर इसकी घोषणा करेंगे। शिवकुमार ने सोशल वैल्फेयर मिनिस्टर डा. एच.सी. महादेवप्पा के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, जिन्होंने कहा था कि कर्नाटक में पावर-शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में नेतृत्व मजबूत हैं और इसमें बदलाव की संभावना से इंकार किया। हालांकि, शिवकुमार ने कहा कि वह महादेवप्पा या दूसरे नेताओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस बीच, चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया के वफादार कहे जाने वाले 22 कांग्रेसी विधायक अपने खर्चे पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्राइवेट टूर पर जाने के लिए एक साथ आए हैं, जबकि विधायकों का दूसरा बैच भी उनके साथ जाने के लिए तैयार है। इस कदम को बड़े पैमाने पर सिद्धारमैया की यह संकेत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि उनके पास कांग्रेस विधायकों के बहुमत का सपोर्ट है। शिवकुमार 'टॉप पोस्ट' के लिए फोकस में बने रहना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस हाईकमान ने केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में आने वाले असैंबली इलैक्शन खत्म होने तक वेट एंड वॉच अप्रोच का संकेत दिया है। असम असैंबली इलैक्शन से पहले, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार के खिलाफ 20 प्वॉइंट चार्जशीट जारी की है और प्रशासन पर करप्शन में लिप्त होने और अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने के लिए अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

राज्यसभा चुनाव के वर्षपर्यंत सियासी मायने

कमलेश पांडे

चिरंजीवी सदन %राज्यसभा% के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटें के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।

जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहां तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उत्तरप्रदेश की 10 और झारखंड, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना आदि की 20 से अधिक सीटों के लिए नवम्बर में चुनाव होंगे।

जहां तक उच्च सदन राज्यसभा में वर्तमान दलगत स्थिति की बात है तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जहां भाजपा के 103 और एनडीए के 121-129 सांसद हैं। जबकि विपक्षी इंडिया (ढ्ढहृष्ठढ्ढ) ब्लॉक के पास 78-80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 27 सांसद हैं। जहां तक इन चुनावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो इन चुनावों में एनडीए को 7-9 या इससे अधिक सीटों का लाभ मिलने का अनुमान है, जिससे उनकी संख्या 145 तक पहुंच सकती है। जबकि विपक्ष को 5 सीटें खोने का खतरा, खासकर बिहार, महाराष्ट्र में है। इससे भाजपा को राज्यसभा में अब कोई भी विधेयक पास करना आसान होगा और सुपरमेजॉरिटी की ओर बढ़त भी उसे मिलेगी।

सवाल है कि इन चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की संभावना है तो

राजनीतिक विश्लेषकों को अनुमान है कि एनडीए को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 48 या इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनकी ताकत 129 से बढ़कर 140+ हो सकती है। पहले चरण के 37 सीटों पर 5-7 का लाभ अनुमानित है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बाद के चरणों से भी उसे अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, 71-75 खाली सीटों में से एनडीए को नेट 7-9 या 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान में एनडीए के 121-129 सदस्य हैं, इसलिए चुनाव बाद 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बाद के जून-नवम्बर वाले दूसरे चरणों के प्रभाव की बात है तो वे भी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में भाजपा को 7-8 मिलनी संभावित है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना आदि में स्थिरतामिलेगी।, कुल मिलाकर सुपरमेजॉरिटी (123+) पक्की होगी। जबकि विपक्ष को 5 नुकसान होगा।

जहां तक इन चुनावों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की बात हैं तो इंडिया गठबंधन को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 71-75 सीटों में से नेट 5 का नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी संख्या 80 से घटकर 75 रह जाएगी। पहले चरण के 37 सीटों पर भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है, हालांकि कुछ राज्यों में स्थिरता संभव है। विश्लेषकों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक वर्तमान 80 सीटों से 75 पर सिमट सकता है। कांग्रेस को विशेष रूप से 8 सीटें खोने का खतरा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह की सीटें भी शामिल हैं। वहीं बाद के चरणों का प्रभाव भी उसपर पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें में से सपा को 2-3 मिलनी संभावित हैं, लेकिन कुल नुकसान होगा। जबकि कर्नाटक, झारखंड में 1-1 सीटों का नुकसान संभव है। ओवरऑल, एनडीए के लाभ से इंडिया कमजोर होगा।

जहां तक राज्यवार स्थिति की बात है तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और एक सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और एनडीए के खाते में 4 सीटें सुनिश्चित हैं, जबकि 5 के लिए जोर आजमाइश बढ़ेगी। क्योंकि यहां 35 सीटों के साथ ढ्ढ.हृ.ष्ठ.ढ्ढ.. एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में 5 विधायकों वाले ,ढ्ढरूढ्ढरू की भूमिका अहम हो जाती है। यदि पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो बिहार में विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हो जाते हैं और विपक्ष एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व और विपक्षी एकता की के लिए अग्निपरीक्षा होगा।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे, जहां अभी 2 सीट बीजेपी और 2 बीजेडी के पास है लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और यहां भी बीजेपी जीत दर्ज करने की स्थिति में है।

रही बात तेलंगाना की तो वहां से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी रिटायर हो रहे हैं और बीआरएस के एक कैंडिडेट का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस दोनों सीटें जीत सकती है और हिमाचल में भी कांग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम से तीन पश्चिम बंगाल से 5 और तमिलनाडु से भी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चूंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के पास राज्यसभा में अपना संख्याबल कायम रखने का मौका मिलेगा।

यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग से निपटने की चुनौती विपक्ष के सामने रहेगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने अपने विधायको को एकजुट रखने की चुनौती हमेशा होती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। इसलिए आने वाले राज्यसभा चुनावों को देखें तो चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यहां पर काग्रेस और सहयोगी दलों को फूंक-फूंक करकदम रखना होगा। हालांकि कुछ सीटों पर तो रिजल्ट पहले से ही तय है, लेकिन अगर विपक्ष क्रॉस वोटिंग को रोक पाता है तो उसके हाथ भी कुछ सीट आ सकतीहैं। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष 75 सीटों पर होने वाले चुनावों में विपक्ष यदि कारगर रणनीति नहीं बनाता है तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संख्या और घट सकती है, इतना तय है।

जहां तक इन चुनावों में प्रमुख नेताओं के प्रभावित होने की बात है तो कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जदयू नेता हरिवंश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (6 मंत्री सहित) शामिल हैं। वहीं बीएसपी राज्यसभा से साफ हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं राजद (ऋछ्वष्ठ) और बीजद (क्चछ्वष्ठ) समेत कई दलों की सीटें घटेगी।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

सो पौराणिक शब्दों में चन्द्रमा रूप शिव भगवान् के आग्रह करने पर विष्णु रूप आग्नेय वाष्प ने, घनीभाव को प्राप्त होकर पृथ्वी पिण्डरूप मोहिनी स्वरूप धारण किया।

, पृथ्वीपिण्ड के सुस्थिर हो जाने पर और अन्यान्य ग्रहों के आकर्षण विकर्षण के तारतम्य से पृथ्वी की भी स्वतन्त्र कक्षा नियत हो जाने पर चन्द्रपिण्ड पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा, मानो शिव भगवान् मोहिनी रूप पृथ्वी के रूप लावण्य को देख कर उस पर लट्टूग हो गये। यही महादेव का मोहिनी के पीछे भागनेका अभिप्राय है; चांद ने भरपेट दौड़धूप की, अपने कर किरण किंवा हाथ फैलाये, परन्तु कुछ भी पल्ले न पड़ सका, अर्थात् वह चन्द्रपिण्ड पृथ्वी पिण्ड को आत्मसात् न कर सका यही मोहिनी के हाथ न आने का तात्पर्य है।

वर्तमान विज्ञानवेत्ता भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि आरम्भमें यह पृथ्वी तपे हुवे सोने के बराबर जाज्वल्यमान एवं दमकते हुवे पिण्ड के समान थी सो ज्यों ही चांद पृथ्वीपिण्ड की अपरिमित ऊष्मा से संश्लिष्ट हुवा तो उसका बहुत सा भास्वर हिम पिघल पिघल कर बहने लगा। गर्मी के संयोग से बर्फ का बह जाना विज्ञान सिद्ध बात है। सो यही शिव के वीर्यपात का श्राशय है।

चन्द्रमा से गिरा हुआ वह करोडो मन भास्वर हिम आकाशस्थ आग्नेय वाष्प के संमिश्रण से देदीप्यमान कलल की सूरत में पृथिवी के अमुक अमुक भागों में समा गया। जिस अंश में आग्नेय वाष्प का अधिक भाग मिल गया वह सोना बन गया और जिसमें हिम का अधिक भाग रहा वह चांदी बन गई। इसी तरह अन्यान्य तत्त्वों के न्यूनाधिक विमिश्रण के तारतम्य से ततदू घातुओं की उत्पत्ति हुई। यही इस आख्यायिका का वास्तविक भाव है।

क्रमशः ...

रॉबर्ट बैडेन-पावेल की प्रेरणा से सेवा और नेतृत्व का संदेश

सुनील कुमार महला

22 फरवरी को स्काउट संस्थापक दिवस या संस्थापक दिवस (फाउंडर्स डे) के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस स्काउट आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन-पावेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा स्काउट्स और गाइड्स के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दिन उनकी पत्नी तथा विश्व प्रमुख गाइड ओलेव बैडेन-पॉवेल का भी जन्मदिन होता है।

पाठकों को बताता चलूं कि भारत में इसे अक्सर विश्व चिंतन दिवस (वर्ल्ड थिंकिंग डे) के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि स्काउट्स प्यार से संस्थापक को बी.पी. भी कहते हैं। इस दिन स्काउट और गाइड अपने नियम और प्रतिज्ञा(स्काउट प्रॉमिस)को दोहराते हैं तथा करोड़ों स्काउट यूनिफॉर्म पहनकर समाज सेवा के कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दिन स्काउट और गाइड्स द्वारा सामुदायिक सेवा, रक्तदान, धन जुटाने, ध्वजारोहण और रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस दिवस का महत्व यह है कि यह दिवस स्काउटिंग के उन मूल्यों (अनुशासन, देशभक्ति, सेवा) को पुनर्जीवित करता है, जो युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यदि हम यहां पर स्काउटिंग,जिसे शांति और भाईचारे का उत्सव भी कहा जाता है, के इतिहास पर नजर डालें तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्काउटिंग की शुरुआत एक प्रयोगात्मक कैंप से हुई थी।

दरअसल, लॉर्ड बेडन पॉवेल ने इंग्लैंड के ब्राउंसी द्वीप पर वर्ष 1907 में पहला कैंप लगाया था। गौरतलब है कि स्काउटिंग की शुरुआत किसी खेल या शौक के रूप में नहीं हुई थी। बैडेन-पॉवेल ने अपने सैन्य अनुभवों से प्रेरणा लेकर युवाओं में चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। पाठकों को बताता चलूं कि स्काउट सैल्यूट के पीछे भी एक अर्थ है। दरअसल,तीन उंगलियों वाला स्काउट सलाम तीन मूल सिद्धांतों क्रमशः ईश्वर और देश के प्रति कर्तव्य, दूसरों की मदद तथा स्काउट नियमों के पालन का प्रतीक है।

उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के स्काउट्स एक-दूसरे से बाएं हाथ (लेफ्ट हैंड) से हाथ मिलाते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि बायां हाथ दिल के करीब होता है और यह गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा, युद्ध के समय योद्धा अपना बचाव करने वाली ढाल (शील्ड) बाएं हाथ में रखते थे; बाएं हाथ से हाथ मिलाने का मतलब था ढाल को नीचे रखना, जो सामने वाले पर पूर्ण विश्वास को दर्शाता है।

पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एक ईगल स्काउट थे। वे अपने साथ चंद्रमा पर स्काउटिंग का बैज भी ले गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार, चंद्रमा पर जाने वाले 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से 11 किसी न किसी रूप में स्काउटिंग से जुड़े रहे थे। बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि स्काउट जो गले में स्कार्फ पहनते हैं, वह सिर्फ वर्दी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं।

पैक्स सिलिका में शामिल होकर भारत ने चीन को बेचैन कर दिया?

नीरज कुमार दुबे

भारत ने आज अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ते हुए एक अहम रणनीतिक कदम उठाया। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अवसर पर दोनों देशों ने पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भरोसेमंद और लचीला सहयोग तंत्र विकसित करना है।

हम आपको बता दें कि पैक्स सिलिका अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख ढांचा है, जिसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में भरोसेमंद साझेदारों का नेटवर्क बनाना है। घोषणा पत्र में आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को दीर्घकालिक वैश्विक समृद्धि का परिवर्तनकारी साधन बताया गया है।

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी।

वैष्णव ने बताया कि भारतीय इंजीनियर उन्नत दो नैनोमीटर चिप डिजाइन पर काम कर रहे हैं। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को लगभग दस लाख अतिरिक्त कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी और भारत इस प्रतिभा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र बन सकता है। छात्रों को विश्वस्तरीय चिप डिजाइन उपकरण निशुल्क उपलब्ध कराए जाने की बात भी उन्होंने कही।

इस अवसर पर बोलते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे वैश्विक प्रौद्योगिकी व्यवस्था में एक निर्णायक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का संकल्प और आत्मनिर्भर मार्ग चुनने की

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में दीर्घकालिक चक्रवृद्धि विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह सोच 1947 से निरंतर बनी रहती तो आज स्थिति अलग होती, लेकिन अब भी शुरुआत होने पर अगली पीढ़ियां इसका लाभ उठाएंगी।

इच्छा इस साझेदारी को विशिष्ट बनाती है। व्यापार समझौते से लेकर रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग तक दोनों देशों के बीच असीम संभावनाएं हैं।

अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप सचिव जैकब हेलबर्ग ने इसे भू राजनीतिक संदर्भ में रखा। उन्होंने कहा कि यह पहल हथियारबंद निर्भरता और दबाव आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्वीकार करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह देखा जाना चाहिए।

हम आपको बता दें कि घोषणा पत्र में ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इजरायल, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूएई और ब्रिटेन जैसे देशों के हस्ताक्षर हैं। कनाडा, नीदरलैंड, यूरोपीय संघ, ओईसीडी और ताइवान जैसे प्रतिभागी भी इस ढांचे से जुड़े हैं। यह पहल खनिज उत्खनन से लेकर चिप निर्माण और एआई तैनाती तक पूरी प्रौद्योगिकी श्रृंखला को सुरक्षित करने की परिकल्पना करती है।

हाल में दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौता भी संपन्न हुआ, जिसने पुराने मतभेदों को दूर कर आर्थिक एकीकरण की आधारशिला रखी। इससे पहले भारत ने वाशिंगटन में आयोजित क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में भाग लेते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम कम करने और अत्यधिक केंद्रीकरण से बचने पर जोर दिया था।

देखा जाए तो भारत का पैक्स सिलिका से जुड़ना सामरिक दृष्टि से दूरगामी महत्व का कदम है। आज विश्व व्यवस्था में प्रौद्योगिकी शक्ति ही वास्तविक शक्ति का आधार बन रही है। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण किसी भी राष्ट्र की आर्थिक और सैन्य क्षमता को प्रभावित करता है।

चीन और अमेरिका के बीच प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को खंडित किया है। ऐसे समय में भारत का एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक तकनीकी गठबंधन का हिस्सा बनना उसे रणनीतिक लाभ देता है। इससे भारत को उन्नत चिप निर्माण, डिजाइन क्षमता और एआई अनुसंधान में निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर मिल सकते हैं।

इसके सामरिक निहितार्थ भी स्पष्ट हैं क्योंकि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी प्रणालियों के लिए उन्नत चिप और एआई क्षमता अनिवार्य है। यदि भारत आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनता है, तो उसे संवेदनशील प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर निर्माण में विविधीकरण से चीन पर निर्भरता कम करने की पश्चिमी रणनीति में भारत की भूमिका मजबूत होगी।

साथ ही, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के संदर्भ में यह साझेदारी भारत को आर्थिक और तकनीकी आधार प्रदान करेगी, जिससे वह अपने सामरिक हितों की रक्षा कर सके। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने की अमेरिकी सोच भारत के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक युद्ध और भू राजनीति में डिजिटल अवसंरचना और डेटा केंद्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पारंपरिक सैन्य साधन।

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण अत्यधिक पूंजी और तकनीकी परिशुद्धता मांगता है। यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व का लक्ष्य पाना है तो उसे नीतिगत स्थिरता, अनुसंधान निवेश और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी एक ध्रुव पर अत्यधिक निर्भर न हो।

बहरहाल, पैक्स सिलिका में भारत की भागीदारी एक अवसर है, जिससे वह 21वीं सदी की तकनीकी व्यवस्था में सक्रिय निर्माता की भूमिका निभा सकता है। यह कदम भारत को केवल बाजार नहीं, बल्कि मानक निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में है। यदि इस पहल को दीर्घकालिक रणनीति और घरेलू सुधारों के साथ जोड़ा गया, तो आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक और सामरिक स्थिति कहीं अधिक सुदृढ़ हो सकती है।

आज का इतिहास

1887 संघ लेबर पार्टी सिनसिनाटी में आयोजित की गयी।

1899 फिलीपीन-अमेरिकी युद्ध- फिलिपिनो बलों ने अमेरिकियों से मनीला पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक असफल प्रयास में अपना पहला पलटवार शुरू किया।

1909 कनेक्टिकट की अगुवाई में ग्रेट व्हाइटफ्लेट के सोलह संयुक्त राज्य नौसेना युद्धपोतों ने विश्व का एक पूर्वनिर्धारण पूरा किया।

1913 मैक्सिको के क्रान्तिकरी राष्टपति फ़्रैन्सिसको मैडेरो की सेना ने हत्या कर दी। इस घटना में उनके साथ उप-राष्ट्रपति पीनो स्वेरेज़ की भी हत्या हो गयी।

1949 सिनसिनाटी गार्डन सिनसिनाटी शहर में खोला गया।

1956 एल्विस प्रेस्ली ने हार्टब्रेक होटल में पहली बार संयुक्त राज्य संगीत चार्ट में प्रवेश किया।

1958 मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासर और सीरियाई राष्ट्रपति शुकरी अल-क्वातली ने संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए एक संघ संधि पर हस्ताक्षर किए।

1979 यूनाइटेड किंगडम ने सेंट लूसिया को स्वतंत्रता प्रदान की।

1980 अफगानिस्तान में सैनिक शासन लागू होने की घोषणा हुई।

1980 न्यूयॉर्क के लेक प्लासीड में शीतकालीन ओलंपिक में, यूनाइटेडस्टेट्स आइस हॉकी टीम ने सोवियत संघ को हरा दिया एक अप्रत्याशित जीत में बर्फ पर चमत्कार के रूप में जाना जाता है।

1983 नाटक मूस मर्डर्स उसी रात न्यूयॉर्क सिटी के यूजीन ओ%नील थियेटर में खोला और बंद किया गया, जो %वेवनेस% का मानक बन गया, जिसके खिलाफ सभी ब्रॉडवे थिएटर विफलताओं को आंका जाता है।

1995 अमेरिकी राष्ट्रपति बिलक्लिंटन द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के तहत कोरोना जासूस उपग्रह कार्यक्रम द्वारा खींची गई तस्वीरों को हटा दिया गया था।

1996 अभिनेत्री हेले बेरी ने डेविड जस्टिस से तलाक लिया।

1997 स्कॉटलैंड के रोसलिन संस्थान में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पहली बार किसी स्तनधारी जीव से निकाली गई कोशिका से क्लोन बनाने की घोषणा की।

1998 1998 शीतकालीन ओलंपिक जापान में नागानो में आयोजित किया गया।

2006 कम से कम छह पुरुषों ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी नकदी डकैती का मंचन किया, जो कि केंट के टोनब्रिज में एक सिक्यूरिटीज डिपो से बैंक नोटों में 53,116,760 चोरी कर रहा था।

2010 ग्रीस और यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीस के लिए 20 - 25 बिलियन यूरो की वित्तीय सहायता योजना की योजना बनायी गयी।

संसद में गतिरोध बने रहना चिंता का विषय

नीरजा चौधरी

वर्षों से संसद के कामकाज में आयी गिरावट हमारी सामूहिक चिंता का कारण बनती जा रही है। कई बार बिना चर्चा के ही संसद में बिल पारित हो जाते हैं। संसद चल रही होती है, और माननीय सदस्यगण अध्यक्ष के आसन तक पहुंच जाते हैं। वे एक-दूसरे पर कागज फेंकते हैं। संसदीय कार्यवाही कई दिनों तक रुक जाती है और पीठासीन अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप लगाये जाते हैं। ये सब अब संसदीय आचरण का हिस्सा बन चुके हैं। इसके बावजूद बजट सत्र के पहले चरण में जो हुआ, वह बेहद चिंताजनक है।

विपक्ष के 118 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। भले ही अध्यक्ष को हटाने के लिए जरूरी संख्याबल विपक्ष के पास न हो, लेकिन इससे लोकसभा अध्यक्ष की छवि प्रभावित होती है। वर्षों के संसदीय इतिहास में विपक्ष ने यह कदम उठाने के बारे में सोचा न था। उतना ही अभूतपूर्व वह कदम था, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने से रोका। उनके पास ठोस सूचना थी कि प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, वहां कांग्रेस की महिला सांसद बाधा पहुंचाने का काम कर सकती हैं।

दूसरे शब्दों में, लोकसभा अध्यक्ष चिंतित थे कि प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए लोकसभा में उनका आना सुरक्षित नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की यह सूचना सुरक्षा के लिहाज से बेहद चौंकाने वाली थी। गौरतलब है कि 2024 के मध्य से वॉच एंड वार्ड स्टाफ नहीं, बल्कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) पर संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर सरकार की तरफ से किसी भी तरह यह संदेश जाये कि प्रधानमंत्री लोकसभा में सुरक्षित नहीं, तो यह बेहद गंभीर मामला है।

दूसरी तरफ, सरकार पर सुर्खियां बटोरने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशिक पुस्तक, 'फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी' का जिक्र करते हुए 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना की आक्रामकता के बरक्स केंद्र सरकार की कथित रक्षात्मकता का मुद्दा उठाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि प्रकाशक ने इस पुस्तक के प्रकाशित न होने की जानकारी दी, तथा नरवणे ने भी प्रकाशक के रुख से सहमति जतायी, ऐसे में, स्थिति विस्फोटक हो गयी। स्थिति तब और जटिल हो गयी, जब एक एफआइआर दर्ज हो गयी और सदन में बहस किताब में दर्ज मुद्दे के बजाय इस पर केंद्रित हो गयी कि राहुल गांधी के पास यह किताब आयी कहां से। सदन

में राहुल गांधी के भाषण के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास कराया। उन्होंने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग करने के साथ उन पर जीवनभर चुनाव लड़ने से प्रतिबंध लगाने की भी मांग की।

इन घटनाक्रमों के कारण संसद की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं- यानी नेता प्रतिपक्ष तथा लोकसभा अध्यक्ष की छवि प्रभावित हुई। इसने एक बार फिर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच भरोसे की कमी की रेखांकित किया, जिस कारण संसद ही नहीं चल पायी। इस कारण सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद भी कठिन हो गया। बेशक संसद को सुचारु तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है। लेकिन यह विपक्ष के सहयोग या आपसी संवाद में शालीनता के बगैर संभव नहीं है।

संसद में गतिरोध पैदा होना कोई नया नहीं है। मुझे 1996 का एक दृश्य याद आता है, जब सदन में भारी शोरगुल से परेशान तत्कालीन गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त संसद के सेंट्रल हॉल के दरवाजे के पास हाथों में अपना सिर टिकाये परेशान और निरुपाय बैठे थे। गठबंधन सरकारों के दौर में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच की असहमति से संसद के कामकाज में बार-बार गतिरोध पैदा होते थे। उस दौर में क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गयी थीं, और उनके सांसद जब-तब संसद ठप कर अपने प्रमुखों को यह संदेश देते थे कि वे दिल्ली में अपने राज्य के हितों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुझे याद है कि दिसंबर, 2011 में लोकपाल बिल का विरोध करते हुए राजद के एक सांसद ने बिल की प्रति फाड़ दी थी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद उस दिन विजिटर्स गैलरी में बैठे अपने सांसदों को देख रहे थे। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुस्से में प्रदर्शन करते सांसदों को फटकारते हुए कहा था, 'ईश्वर के लिए, अपना काम कीजिए'। अतीत में जब भी कभी संसद में गतिरोध पैदा होता था, तब पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही स्थगित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अपने कक्ष में बुलाकर संयम बरतने और सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए रास्ता निकालने की बात कहते थे। वैसे प्रयास अक्सर सफल होते थे, क्योंकि पीठासीन अधिकारी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे।

इसके अलावा, तब दोनों ही ओर ऐसे कई नेता थे, जो संसद की गरिमा में विश्वास करते थे और चाहते थे कि संसद चले। तब हमारे संसदीय लोकतंत्र की क्या छवि थी? इसके उत्तर भी संसद से ही मिलते हैं। उस दौर के अनेक सांसदों के यादगार भाषण सुरक्षित हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच स्वस्थ रिश्तों की स्मृतियों की एक झलक स्वर्गीय सुषमा स्वराज के 2014 के एक भाषण से मिलती है, जब वह नेता प्रतिपक्ष थीं। सुषमा स्वराज ने 15वीं लोकसभा के विघटित होने से ठीक पहले जो कुछ कहा था, वह आज के संदर्भ में ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा था, 'भाई कमलनाथ अपनी शरारत से इस सदन को उलझा देते थे और आदरणीय शिंदे जी (सुशील कुमार शिंदे) अपनी शराफत से उसे सुलझा देते थे'।

उसके बाद सुषमा स्वराज ने संकट के समय मध्यस्थता के लिए सोनिया गांधी की प्रशंसा की। जबकि अतीत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में इन्हीं सुषमा स्वराज ने अपना सिर मुड़वा लेने की धमकी दी थी। फिर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनकी विनम्रता, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को उनकी सहिष्णुता और लालकृष्ण आडवाणी को उनकी न्यायप्रियता के लिए धन्यवाद दिया। जाहिर है, संसदीय गतिरोध के समय इन सबकी भूमिका उल्लेखनीय थी। सुषमा स्वराज ने कहा था कि 'भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख भावना यह है कि विपक्ष में होते हुए भी हम शत्रु नहीं हैं'। इसीलिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद संबंध बनाये रखना संभव हो सका। सुषमा स्वराज के ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि वे बारह साल पहले थे।

यूपी से शुरू हुआ असली-नकली हिंदू कौन?

सनत जैन

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा, कि मुख्यमंत्री योगी ने 20 दिन में निर्णय नहीं लिया तो वह लखनऊ की ओर कूच करेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगा था। शंकराचार्य ने गो-रक्षा के मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहा था। उनकी इस मांग पर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 20 दिन बीत जाने के बावजूद योगी ने ना तो हिंदू होने का प्रमाण दिया है ना ही गौ रक्षा के मामले में कोई ठोस निर्णय ही सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को चेतावनी दी है, यदि तय समय सीमा में कदम नहीं उठाया गया तो वह 11 मार्च तक लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रयागराज में हुई घटना में बटुकों के साथ कथित बदसलूकी, मारपीट और ज्यादती को लेकर उत्तर प्रदेश के दो उपमुख्यमंत्री योगी के विरोध में खड़े हो गए हैं। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने घर पर बटुकों को बुलाकर उनका सम्मान किया है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा और संघ की स्थिति चिंताजनक हो गई है। भारतीय राजनीति में 80 और 20 का समीकरण बनाकर हिंदुओं को एकजुट करने का जो प्रयास किया गया था, वह उत्तर प्रदेश से ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। यूजीसी ने जो नए नियम लागू किए थे, उसके बाद हिंदुओं में सामान्य जातियों, पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी को लेकर हिंदू बिखरने की स्थिति में आ गए हैं। रही-सही कसर शंकराचार्य और योगी महाराज के बीच जो विवाद चल रहा है, उसस हिंदुओं का हर वर्ग नाराज नजर आ रहा है। शंकराचार्य के साथ योगी के विवाद तथा यूजीसी की अधिसूचना के बाद हिंदुओं में बिखराव का एक नया दौर शुरू हो गया है। भारतीय राजनीति एक बार फिर से अलग करवट लेने जा रही है। ब्राह्मण और दलित समुदाय के उपमुख्यमंत्री खुलकर शंकराचार्य के साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नई राजनीतिक चुनौती मिलना शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में संघ और भाजपा दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत को उत्तर प्रदेश की यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद भी विवाद सुलझने के स्थान पर उलझता चला जा रहा है। राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ विधायकों का एक बड़ा समूह योगी के विरोध में खड़ा हो गया है। जिससे स्पष्ट है, मामला गंभीर है। ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को शंकराचार्य को लेकर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। उत्तर प्रदेश में दलित, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्ग और ब्राह्मण भाजपा से नाराज हैं। अब असली और नकली हिंदुओं की बात होने लगी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था। गौ हत्या और को मांस के निर्यात को लेकर अब शंकराचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से योगी और हिंदू होने का प्रमाण मांग कर भाजपा के लिए एक परेशानी खड़ी कर दी है। शंकराचार्य ने कहा मुख्यमंत्री योगी ने सनातन और हिंदुओं के विरुद्ध जो कचरा फैलाया है। उसे भाजपा को स्वयं साफ करना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखाती वह हिंदुओं और सनातन मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तब तक संत समाज को भाजपा के हिंदुत्व पर अब विश्वास नहीं होगा। शंकराचार्य के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर होना तय है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानकर चल रहे हैं, भाजपा ने हिंदू वर्सेस अल्पसंख्यक का जो धार्मिक ध्रुवीकरण तैयार कर हिंदुओं को एकजुट किया था अब उसके बिखरने का समय आ गया है। हिंदू धर्म के शीर्ष पर बैठे शंकराचार्य जब सार्वजनिक नाराजगी व्यक्त करने लगे और योगी जैसे मठाधीश को जब हिंदू मानने से इनकार कर दें ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने संसद के अंदर जो असली और नकली हिंदू का मामला उठाया था अब इस मामले को शंकराचार्य हवा दे रहे हैं।

एआई समिट की चमक और जमीनी हकीकत

सनत जैन

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर बड़े-बड़े दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्ष एआई विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, खबरों के अनुसार उसमें से लगभग 800 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को दर्शाता है। जब देश में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। मंचों से डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, सरकार की इस मामले में वास्तविक सोच क्या है? सरकार ने एआई में शोध के लिए किस तरह की नीतियां बनाई हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शोध के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। इस दौड़ में कैसे भारत आगे रहेगा। इसकी कोई वास्तविक सोच दिख नहीं रही है।

एआई को लेकर भारत सरकार भी सपने देख रही है और वही सपना लोगों को दिखा रही है। विश्वविद्यालयों और आईटी सेक्टर को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। शोध के लिए पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार को बजट में जो धन उपलब्ध कराना था, उसे बढ़ाने के स्थान पर और कम किया है। शोध संस्थानों में बुनियादी ढांचा, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन और दीर्घकालिक अनुदान की कमी होने के कारण शोध लगभग लगभग बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को पर्याप्त प्रोत्साहन नही मिलेगा, तो स्वदेशी एआई तकनीक के साथ कदमताल कर पाना संभव नहीं होगा। भारत एक बाजार बनेगा। जहां पर विदेश से आयातित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा और रोजगार के अवसर विदेशों को देने का काम करेंगे। एआई समिट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी स्वागत योग्य है।

भारत सरकार यदि भारत को एक उपभोक्ता बाजार बनाना चाहती है तो यह भारत सरकार की सोच है। भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए पलक पावड़े बिछाती है। भारतीय कंपनियों और भारतीय शोधकर्ताओं के ऊपर सरकार को विश्वास ही नहीं है। सरकार जो नीतियां बनाती है उनके क्रियान्वयन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कि

भारतीय शोधकर्ता और भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के मुकाबले में पिछड जाती हैं। यह स्थिति दीर्घकालिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। दुनिया की अग्रणी कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारतीय राजनेता और भारतीय नौकरशाह दामाद की तरह स्वागत करते हैं।

भारत सरकार का हर काम इन्हीं कंपनियों को सौंपा जाता है। इनसे अच्छे उत्पादन यदि भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करते हैं। उन्हें सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है, जिसके कारण वह विदेशो में जाकर अपना करियर बनाने के लिए विवश होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला एवं अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के साथ सरकारी संरक्षण को लेकर भारतीय एवं वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। भारत में एआई तकनीकी का विस्तार स्वाभाविक है रूप से समय की मांग है। भारत सरकार को विदेशी कंपनियों के साथ-साथ समानांतर अवसर उपलब्ध कराकर स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। अन्यथा भारत का आयात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आयात में खर्च होगी। व्यापार में आयात और निर्यात के अंतर का घाटा बढ़ता जाएगा। जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होगा।

रक्षा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन में भारत का एआई में सीमित उपयोग चिंता का विषय है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्र एआई को रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहे हैं, एआई में शोध के कई छोटे-छोटे देश भारत सरकार से ज्यादा शोध के लिए आर्थिक सहायता दे रहे हैं। भारत का सबसे कम बजट शोध के लिए है। भारत सरकार को इस क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है। केवल घोषणाओं से तकनीकी के साथ विकास और आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, रुपये की गिरती कीमत के आर्थिक संकेतक यह बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में हम कितने दबाव में हैं। वर्तमान स्थिति में भी यदि तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ती है, तो भारत में महंगाई, बेरोजगारी एवं सामाजिक आर्थिक संतुलन और भी कमजोर होगा। भारत में लाखों की संख्या में स्नातक और परास्नातक बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। वह सरकारी चपरासी की नौकरी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी बड़ी युवा आबादी होने के बाद भी हम उन्हें तकनीकी ज्ञान और रोजगार के अवसर से नहीं जोड़ पा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों को विचारधारा के प्रचार-प्रसार का केंद्र बनाने की स्थान पर विश्वविद्यालयों को नवाचार और अनुसंधान केंद्र के रूप में सशक्त करना समय की सबसे बड़ी चुनौती है। एआई केवल बाजार नहीं, भविष्य के सामाजिक विकास रक्षा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्रांति के लिए एक शक्ति है। भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है, तो उसे केवल उपभोक्ता और बाजार उपलब्ध नहीं कराना है। बल्कि भारत को हर क्षेत्र में निर्माता बनाने की दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों को खुली छूट देनी होगी।

शोध के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी होगी। भारत के अंदर ही उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सरकार जो नीतियां बना रही हैं उसका वास्तविक लाभ भारतीयों को मिल रहा है या नहीं यह देखने का काम भी सरकार का है। भारत सरकार को नवाचार की दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। चीन, जापान जैसे देशों ने इंटरनेट के समानांतर इंटरा-नेट पर भी बहुत बड़ा काम कर रखा है। उन्होंने अपनी भाषा में डिजिटल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एआई युक्त संचार माध्यमों का विकास करके तकनीकी का उपयोग सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है। भारत के सरकारी कामकाज में इस तरह की कोई संस्कृति नहीं है। हम विदेशियों के पीछे आंख बंद करके भाग रहे हैं। हमें स्वदेशियों के लिए भी आंखों को खोलना पड़ेगा। तभी हम वैश्विक स्तर पर अन्य देशों का मुकाबला कर पाएंगे।

बांग्लादेश के साथ नई शुरुआत की उम्मीद

प्रभु चावला

दक्षिण एशिया की ज्यामिति में भूगोल ही नियति है और स्मृति कभी जड़ नहीं होती। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी भर नहीं है, यह भारत की महाद्वीपीय सुरक्षा का पूर्वी आधार स्तंभ और उन साझा जल संसाधनों का संरक्षक है, जो आधे अरब जीवन को सींचते हैं। यह बंगाल की खाड़ी के विस्तृत होते रणनीतिक रंगमंच का प्रवेश द्वार भी है। इसलिए ढाका में जो कुछ भी घटित होता है, उसकी गूंज इसके डेल्टा मैदानी इलाकों से बहुत दूर तक जाती है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला दिया, जिसकी गूंज भूकंपीय बदलाव की तरह थी। तारिक रहमान की बीएनपी ने चुनाव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया।

शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले 2024 के 'जेन जी' विद्रोह से जन्मा और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला अंतरिम प्रशासन अब इतिहास बन गया है। तीन दशकों से अधिक के महिला वर्चस्व के बाद एक पुरुष ढाका में प्रधानमंत्री पद संभाल रहा है। कभी एक अनिच्छुक सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी अब लगभग 70 सीटों के साथ विपक्ष का नेतृत्व कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वास्तविकता स्पष्ट रूप से पहचानी है। नतीजा सामने आने के कुछ ही घंटों के भीतर तारिक रहमान को फोन कर बधाई देने वाले वह पहले शासनाध्यक्षों में से थे। यह पहल एक लोकतांत्रिक, स्थिर और समावेशी बांग्लादेश के साथ काम करने की भारत की तत्परता को रेखांकित करती है। मीडिया विशेषज्ञों के लिए बांग्लादेश का यह घटनाक्रम शेख हसीना के बाद के अंतराल की बर्बरता की निर्मम राष्ट्रीय जांच, अल्पसंख्यकों की गरिमा पर एक बाध्यकारी जनमत संग्रह तथा आर्थिक सुधार, व्यावहारिक शासन और राष्ट्रीय नवीनीकरण पर केंद्रित 'बांग्लादेश फर्स्ट' सिद्धांत की एक गूंजती हुई पुष्टि है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के खिलाफ आतंक के सुनियोजित शासन में डूब गया था। वैश्विक संस्थानों ने पहले 100 दिनों में ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर 2000 से अधिक हमले दर्ज किए थे, जिससे हजारों लोग भारत आने को मजबूर हुए। खुद

मोहम्मद यूनुस द्वारा आमंत्रित एक संयुक्त राष्ट्र जांच समिति ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के अंतरिम शासन के इनकार को खारिज कर दिया। भारतीय स्क्रीन पर विस्थापित परिवारों, नष्ट किए गए मंदिरों और शिकार होते श्रद्धालुओं के दृश्यों ने द्विपक्षीय संबंधों को आक्रोश की भट्टी में बदल दिया।

भारत द्वारा बेदखल प्रधानमंत्री हसीना को शरण देने ने द्विपक्षीय दरार को और गहरा किया। हालांकि अपनी मां खालिदा जिया की मृत्यु के बाद लंदन से 17 साल के निर्वासन से लौटे तारिक रहमान ने खुद को संप्रभुता के रक्षक के रूप में पेश किया। एक संबोधन में उन्होंने राष्ट्र को पहाड़ियों और मैदानों, मुसलमानों, हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों की एक साझा विरासत घोषित किया,

और जोर दिया कि हर नागरिक को बिना डरे सड़कों पर चलना चाहिए। जमात के संभावित शासन के डर ने इस संदेश को पुरअसर बनाया। करीब तीन दर्जन हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में, जो कभी अवामी लीग के गढ़ थे, नौ प्रतिशत हिंदू मतदाताओं ने निर्णायक रूप से बीएनपी का साथ दिया। उन्होंने तारिक रहमान की पार्टी को उन नेटवर्कों के खिलाफ इकलौती सक्षम ढाल के रूप में देखा,

जिन्होंने उन्हें 18 महीनों तक आतंकित किया था। बांग्लादेश के चुनावी नतीजे से एक असंभव गठबंधन बना। सुरक्षा चाहने वाले अल्पसंख्यक, गरिमा और नौकरियों की मांग करने वाले युवा तथा वंशानुगत शासन व पश्चिमी संरक्षण को खारिज करने वाले रूढ़िवादी मुसलमान एक साथ आ गए। चुनौती हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है।

जमात और उसके सहयोगियों के पास 77 सीटों के साथ एक कठोर वैचारिक मशीनरी भी है। ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने भारत की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में अपना सबसे मजबूत समर्थन हासिल किया, जिसके गंभीर निहितार्थ हैं। इससे सीमापार घुसपैठ को प्रोत्साहन मिलने का जोखिम है। बीएनपी की जीत बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए एक नाजुक उम्मीद जगाती है। रहमान ने व्यवस्था बहाल करने और सभी धर्मों की सुरक्षा को राज्य के मुख्य कर्तव्य के रूप में स्थापित करने का वादा किया है। शेख हसीना को मानवता के आधार पर दी गई शरण को भारत को दुश्मन के रूप में चित्रित करने का हथियार बनाया गया। ठप पड़ी जल वार्ता से लेकर सांस्कृतिक बहिष्कार और पिछले महीने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय धरती पर मैच खेलने से इनकार के असाधारण निर्णय तक, संबंध पूरी तरह टूट गए। क्रिकेट का जो खेल कभी सेतु था, वह युद्ध का एक और मैदान बन गया।

फिर भी, मोदी द्वारा रहमान के जनादेश की त्वरित मान्यता ने आपसी संबंधों के पुनर्गठन का एक द्वार खोल दिया है। भारत के लिए, बांग्लादेश के नए नेतृत्व का आचरण निर्णायक कारक होगा। क्या तारिक रहमान अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, 2024-25 के अत्याचारों के लिए न्याय दिलाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बांग्लादेश भारत विरोधी विद्रोहियों को पनाह नहीं देगा?

रहमान को चरमपंथी तत्वों से स्पष्ट रूप से संबंध तोड़ने होंगे और भारतीय उग्रवादियों को पनाह देने से इनकार करना होगा। इसके अलावा, ढाका को आपसी रणनीतिक और आर्थिक लाभ के आधार पर एक लेन-देन वाले संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए तथा उस सीमापार टकराव को खारिज करना चाहिए, जिसने बार-बार संबंधों में जहर घोला है। दोनों राष्ट्र भूगोल, इतिहास और साझा नियति से इस तरह बंधे हैं, जिसे विचारधारा मिटा नहीं सकती। बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा कि वह अंतहीन टकराव के पाकिस्तान मॉडल को खारिज कर दे। भारत और बांग्लादेश के एक साथ आने से यह डेल्टा विकास, कनेक्टिविटी और स्थिरता के पावरहाउस के रूप में उभर सकता है।

गलगोटिया विश्वविद्यालय की चूक या सरकार की जल्दबाजी?

सतीश मेहरा

नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता सम्मेलन में प्रस्तुत एक रोबोटिक मॉडल ने भारत की तकनीकी विश्वसनीयता, संस्थागत जवाबदेही और सरकारी सत्यापन प्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मंच पर प्रदर्शित रोबोट को भारत की स्वदेशी तकनीकी क्षमता का प्रतीक बताते हुए इसे देश के नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय आई.टी. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस तकनीक की सराहना करते हुए इसे भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का उदाहरण बताया। उस समय यह संदेश दिया गया कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नवप्रवर्तक भी बन चुका है। लेकिन जैसे-जैसे इस मॉडल के तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण सामने आया, कई विशेषज्ञों ने यह संकेत दिया कि रोबोट पूरी तरह स्वायत्त नहीं था और संभवतः बाहरी नियंत्रण या पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग पर आधारित था। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक हो गया कि क्या इस तकनीक को राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने से पहले पर्याप्त तकनीकी सत्यापन किया गया था या नहीं? भारत में किसी भी नई तकनीक, मशीन या मॉडल को कानूनी रूप से पेटेंट देने का अधिकार केवल इंडियन पेटेंट ऑफिस के पास होता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड के अधीन कार्य करता है। जब तक किसी मॉडल को पेटेंट नहीं मिलता, तब तक उसे पूर्ण रूप से प्रमाणित स्वदेशी नवाचार नहीं माना जाता। यदि इस रोबोटिक मॉडल को पेटेंट नहीं मिला था या उसका आवेदन लंबित था, तो इसे राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी प्रक्रिया की दृष्टि से समयपूर्व माना जा सकता है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी जब कोई छात्र या शोधकर्त्ता नया मॉडल विकसित करता है, तो सबसे पहले विश्वविद्यालय का रिसर्च एंड डिवैल्पमैंट या इंटेलैक्चुअल प्रॉपर्टी सैल उसकी जांच करता है। यदि मॉडल सभी मानकों पर खरा उतरता है, तभी उसे पेटैंट प्रदान किया जाता है। इस स्थिति में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि संबंधित मॉडल को पेटैंट या सरकारी तकनीकी मान्यता प्राप्त थी या नहीं। यदि किसी तकनीक को राष्ट्रीय उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो सामान्यतः मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी तथा साइंस एंड टैक्नोलॉजी विभाग जैसे संस्थान उसकी तकनीकी प्रामाणिकता की जांच करते हैं। यदि यह जांच पूरी तरह नहीं हुई और केवल संस्थान के दावे के आधार पर उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत कर दिया गया, तो यह संस्थागत समन्वय की कमी को दर्शाता है। इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंच केवल तकनीकी प्रदर्शन के लिए नहीं होते, बल्कि वे देश की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे मंचों पर प्रस्तुत हर तकनीक केवल एक मॉडल नहीं होती, बल्कि वह देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बन जाती है। यदि उसमें किसी प्रकार की विसंगति सामने आती है, तो उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर देश की छवि पर पड़ता है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विश्व की अग्रणी तकनीकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमता, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन तकनीकी नेतृत्व केवल नवाचार से नहीं, बल्कि उसकी प्रामाणिकता और पारदर्शिता से भी स्थापित होता है। यदि यह केवल विश्वविद्यालय स्तर की प्रस्तुति थी, तो इसे उसी स्तर तक सीमित रखना चाहिए था।

ऐसी करें लौकी की खेती

लौकी एक वार्षिक चढ़ाई वाली बेल है जिसमें जोरदार वृद्धि होती है। पौधे में सफेद रंग के फूल लगते हैं जो मांसल और बोतल के आकार के फल लगते हैं। लौकी का उपयोग खाना पकाने के उद्देश्य से किया जाता है। लौकी के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह बेहतर पाचन में मदद करता है, चीनी के स्तर और कब्ज को कम करता है, अनिद्रा और मूत्र संक्रमण को ठीक करता है और अनिद्रा के इलाज के लिए अच्छा उपाय है।

फसल की किस्म

गोल किस्में : पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मंजरी (संकर किस्म) और पंजाब राउंड

लंबी किस्में : पूसा समर प्रोलिफिक राउंड

बीज दर

500–600 ग्राम प्रति एकड़।

बुवाई का समय

बुवाई का अनुकूल समय फरवरी–मार्च, जून–जुलाई और नवंबर–दिसंबर महीना है।

बीज उपचार

बीज को बाविस्टिन 0.2% 3ग्राम / किलो के साथ मृदा जनित कवक से बीजों को बचाने के लिए उपचारित किया जाता है।

उर्वरक

किलोग्राम/एकड: फार्म यार्ड खाद 20–25 टन / एकड़ प्रति लगायें। यूरिया श्र 60 किग्रा / एकड़ के रूप में नाइट्रोजन श्र 28 किग्रा / एकड़ की उर्वरक खुराक का आवेदन किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन की पहली खुराक श्र 14 किग्रा / एकड़ (यूरिया श्र 30 किग्रा / एकड़) की बुवाई के समय दी जाती है और दूसरी डोज नाइट्रोजन की 14 किग्रा / एकड़ (यूरिया श्र 30 किग्रा / एकड़) की पहली खुराक के समय दी जाती है।

लौकी एक वार्षिक चढ़ाई वाली बेल है जिसमें जोरदार वृद्धि होती है। पौधे में सफेद रंग के फूल लगते हैं जो मांसल और बोतल के आकार के फल लगते हैं। लौकी का उपयोग खाना पकाने के उद्देश्य से किया जाता है। लौकी के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह बेहतर पाचन में मदद करता है, चीनी के स्तर और कब्ज को कम करता है, अनिद्रा और मूत्र संक्रमण को ठीक करता है और अनिद्रा के इलाज के लिए अच्छा उपाय है।

खरपतवार नियंत्रण

खरपतवार की रोकथाम के लिए 2–3 बार निराई गुड़ाई करे, गुड़ाई खाद डालने के समय करें। बरसात के मौसम में खरपतवार की रोकथाम के लिए मिट्टी चढ़ाना भी प्रभावी तरीका है।

सिंचाई

फसल को तत्काल सिंचाई की आवश्यकता होती है। बुवाई के बाद तत्काल सिंचाई दी जाती है। गर्मी के मौसम में 6–7 सिंचाई की आवश्यकता होती है और बरसात के मौसम में अगर जरूरत हो तो सिंचाई दी जाती है। कुल मिलाकर, 9 सिंचाई की आवश्यकता होती है।

विकास के प्रारंभिक चरणों के दौरान 3–4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं, और फूल और फलने के दौरान वैकल्पिक दिन के अनुसार, फर सिंचाई एक आदर्श विधि है। बरसात के मौसम में जल निकासी पौधे के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है।

फसल की अवधि

फसल की अवधि 120 दिन है। जनवरी–मार्च और सितंबर–दिसंबर बोतल लौकी उगाने के लिए आदर्श मौसम हैं।

कटाई का समय

किस्म और मौसम के आधार पर, फसल 60–70 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। बाजार की आवश्यकता के आधार पर, मध्यम और निविदा फल काटे जाते हैं। परिपक्व फल ज्यादातर बीज उत्पादन उद्देश्य के लिए संग्रहीत किए जाते हैं। तेज चाकू की मदद से बेलों से फलों को काटें। तुड़ाई के सीजन में, हर 3–4 दिनों में फलों की तुड़ाई करनी चाहिए।

सफाई और सुखाने

लौकी की अन्य किस्मों से 800 मीटर की दूरी रखें। रोगग्रस्त पौधों को खेत से हटा दें। बीज उत्पादन के लिए, फलों की कटाई तब की जाती है जब वे शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। टाइप टू सीड के उत्पादन के लिए तीन फील्ड निरीक्षण आवश्यक हैं। कटाई के बाद, फलों को सुखाया जाता है और फिर बीज निकाले जाते हैं।

उत्पादन क्षमता

उत्पादन 40–45 टन / हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर भूमि पर खेती करने के लिए लगभग 3–4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।

सहजन की वैज्ञानिक खेती

सहजन बिहार के किसानों के लिए एक बहुवर्षिक सब्जी देनेवाला जाना–पहचाना पौधा है। गाँव देहात में सहजन बिना किसी विशेष देखभाल के किसान अपने घरों के आसपास दो–एक पेड़ लगाकर रखते हैं, जिसके फल का उपयोग वे साल में एक बार जाड़े के दिनों में सब्जी के रूप में करते हैं।

ऐसा देखा जा रहा है कि बाजार में सहजन का फूल, छोटा–नन्हा कोमल सहजन से लेकर बड़ा और मोआसहजन भी ऊँचे दामों में बिकता है। दक्षिण भारतीय लोग सहजन के फूल, फल, पत्ती का उपयोग अपने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में सालों भर करते हैं भारत ही नहीं बल्कि फिलीपिंस, हवाई, मैक्सिको, श्रीलंका, मलेशिया आदि देशों में सहजन विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। सहजन के बीज से तेल भी निकाला जाता है। बीज को उबालकर सुखाने और फिर पाउडर बनाकर विदेशों में निर्यात भी किया जा रहा है। सहजन में औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में है और इसके पौधे के सभी भागों का उपयोग विभिन्न कार्यो में किया जाता है।

मिट्टी

सभी प्रकार की मिट्टियों में सहजन की खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है, परन्तु व्यवसायिक खेती के लिए साल में दो बार फलनेवाला सहजन के प्रभेदों के लिए 6–7.5 पी.एच. मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाया गया है।

सहजन भारतीय मूल का मोरिन्गासाए परिवार का सदस्य है। इसका वनस्पतिक नाम मोरिंगा ओलीफेरा है। सामान्यतया यह एक बहुवर्षिक, कमजोर तना और छोटी–छोटी पत्तियों वाला लगभग दस मीटर से भी उंचा पौधा है। यह कमजोर जमीन पर भी बिना सिंचाई के सालों भर हरा–भरा और तेजी से बढने वाला पौधा है। हाल के दिनों में सहजन का साल में दो बार फलने वाला वार्षिक प्रभेद तैयार किया गया है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन–बी, और विटामिन–सी. से भरपूर है। बिहार के किसानों और खासकर अपनी भू–भागीय पसंद के कारण सहजन दियारा क्षेत्र के किसानों के लिए उनकी फसल प्रणाली का एक आर्थिक महत्व का उपयुक्त फसल हो सकता है।

जलवायु: सामान्यतया 25–300 के औसत तापमान पर सहजन के पौधा का हरा–भरा व काफी फैलने वाला विकास होता है। यह ठंढ को भी सहता है। परन्तु पाला से पौधा को नुकसान होता है। फूल आते समय 400 से ज्यादा तापमान पर फूल झड़ने लगता है। कम या ज्यादा वर्षा से पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। यह विभिन्न पारिस्थितिक अवस्थाओं में उगने वाला एक ढीठ स्वभाव का पौधा है।

सहजन प्रभेद

सहजन का साल में दो बार फलने वाले प्रभेदों में पी.के.एम.1, पी.के.एम.2, कोयेंबटूर 1 तथा कोयेंबटूर 2 प्रमुख हैं। इसका पौधा 4–6 मीटर उंचा होता है तथा 90–100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160–170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधा से 65–170 दोनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधा से 65–70 सें.मी. लम्बा तथा औसतन 6.3 सेंमी. मोटा, 200–400 फल (40–50 किलोग्राम) मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70 प्रतिशत भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4–5 वर्षो तक पेड़ी फसल लिया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से एक मीटर छोड़कर काटना आवश्यक है।

खेत की तैयारी

सहजन के पौध की रोपनी में गड्ढा बनाकर किया जाता है। खेत को अच्छी तरह खरपतवार से साफ़–सफाई का 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 सेंमी. आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे के उपरी मिट्टी के साथ 10 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। इससे खेत पौध के रोपनी हेतु तैयार हो जाता है।

प्रबर्द्धन

सहजन में बीज और शाखा के टुकड़ों दोनों से ही प्रबर्द्धन होता है। अच्छी फलन और साल में दो बार फलन के लिए बीज से प्रबर्द्धन करना अच्छा है। एक हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौध एक महीना में लगाने योग्य तैयार हो जाता है।

शस्य प्रबंधन

एक महीने के तैयार पौध को पहले से तैयार किए गये गड्ढों में माह जुलाई–सितम्बर तक रोपनी कर दें। पौध जब लगभग 75 सेंमी. का हो जाये तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें, इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के तीन महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया + 100 ग्राम सुपर फास्फेट + 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके तीन महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुन: व्यवहार करें। सहजन पर किए गए शोध से यह पाया गया कि मात्र 15 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति गड्ढा तथा एजोसपिरिलम और पी.एस.बी. (5 किलोग्राम/हेक्टेयर) के प्रयोग से जैविक सहजन की खेती, उपज में बिना किसी ह्रास के किया जा सकता है।

सिंचाई

अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रबर्द्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर दोनों ही अवस्था में फूल के झड़ने की समस्या होती है।

पौधा संरक्षण

सहजन पर सबसे ज्यादा आक्रमण बिहार में भुआ पिल्लू नामक कीट से है इसे अगर नियंत्रित नहीं किया जाय तो यह सम्पूर्ण पौधे की पत्तियों को खा जाता है तथा आसपास में भी फ़ैल जाता है। अंडा से निकलने के बाद अपने नवजात अवस्था में यह कीट समूह में एक स्थान पर रहता हैं बाद में भोजन की तलाश में यह सम्पूर्ण पौधों पर बिखर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सरल और देशज उपाय यह है कि कीट के नवजात अवस्था में सर्फ को घोलकर अगर इसके ऊपर डाल दिया जाय तो सभी कीट मर जाते हैं। वयस्क अवस्था में जब यह सम्पूर्ण पौधों पर फ़ैल जाता है तो एकमात्र दवा डाइक्लोरोवास (नूभान) 0.5 मिली. एक लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करने से तत्काल लाभ मिलता है।

सहजन के दूसरे कीट में कभी–कभी फल पर फल मक्खी का आक्रमण होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु भी डाइक्लोरोवास (नूभान) 0.5 मिली. दवा एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने पर कीट का नियंत्रण होता है।

फल की तुड़ाई एवं उपज

साल में दो बार फल देनेवाले सहजन की किस्मों की तुड़ाई सामान्यतया फरवरी–मार्च और सितम्बर–अक्टूबर में होती है। प्रत्येक पौधे से लगभग 200–400 (40–50 किलोग्राम) सहजन सालभर में प्राप्त हो जाता है। सहजन की तुड़ाई बाजार और मात्रा के अनुसार 1–2 माह तक चलता है। सहजन के फल में रेशा आने से पहले ही तुड़ाई करने से बाजार में मांग बनी रहती है और इससे लाभ भी ज्यादा मिलता है।

सहजन का गुण एवं उपयोग

सहजन बहुउपयोगी पौधा है। पौधे के सभी भागों का प्रयोग भोजन, दवा औद्योगिक कार्यो आदि में किया जाता है। सहजन में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व विटामिन है। एक अध्ययन के अनुसार इसमें दूध की तुलना में चार गुणा पोटाशियम तथा संतरा की तुलना में सात गुणा विटामिन सी. है।

सहजन का फूल, फल और पत्तियों का भोजन के रूप में व्यवहार होता है। सहजन का छाल, पत्ती, बीज, गोंद, जड़ आदि से आयुर्वेदिक दवा तैयार किया जाता है, जो लगभग 300 प्रकार के बीमारियों के इलाज में काम आता है। सहजन के पौधा से गूदा निकालकर कपड़ा और कागज उद्योग के काम में व्यवहार किया जाता है।

भारत वर्ष में कई आयुर्वेदिक कम्पनी मुख्यत: 'संजीवन हर्बल' व्यवसायिक रूप से सहजन से दवा बनाकर (पाउडर, कैप्सूल, तेल बीज आदि) विदेशों में निर्यात कर रहे हैं।

दियारा क्षेत्र में सहजन के नये प्रभेदों की खेती को बढ़ावा देकर न सिर्फ स्थानीय व दूर–दराज के बाजारों में सब्जी के रूप में इसका सालों भर बिक्री कर आमदनी कमाया जा सकता है, बल्कि इसके औषधीय व औद्योगिक गुणों पर ध्यान रखते हुए किसानों के बीच में एक स्थाई दीर्घकालीन आमदनी हेतु सोच विकसित किया जा सकता है।

सहजन बिना किसी विशेष देखभाल एवं शून्य लागत पर आमदनी देनी वाली फसल है। किसान भाई अपने घरों के आस–पास अनुपयोगी जमीन पर सहजन के कुछ पौधे लगाकर जहां उन्हें घर के खाने के लिए सब्जी उपलब्ध हो सकेंगी वहीं इसे बेचकर आर्थिक सम्पन्नता भी हासिल कर सकते हैं।

मटर की उन्नत खेती - मटर की खेती से धनवर्षा

भारत की एक महत्वपूर्ण फसल मटर को दलहनों की रानी की संज्ञा प्राप्त है। मटर की खेती, हरी फल्ली, साबूत मटर तथा दाल के लिये की जाती है। मटर की हरी फल्लियाँ सब्जी के लिए तथा सूखे दानों का उपयोग दाल और अन्य भोज्य पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। चाट व छोले बनाने में मटर का विशिष्ट स्थान है। हरी मटर के दानों को सुखाकर या डिब्बा बन्द करके संरक्षित कर बाद में उपयोग किया जाता है। पोषक मान की दृष्टि से मटर के 100 ग्राम दाने में औसतन 11 ग्राम पानी, 22.5 ग्राम प्रोटीन, 1.8 ग्रा. वसा, 62.1 ग्रा. कार्बोहाइड्रेट, 64 मिग्रा. कैल्शियम, 4.8 मिग्रा. लोहा, 0.15 मिग्रा. राइबोफ्लेविन, 0.72 मिग्रा. थाइमिन तथा 2.4 मिग्रा. नियासिन पाया जाता है। फलियाँ निकालने के बाद हरे व सूखे पौधों का उपयोग पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हरी फल्लिओं के लिए मटर की खेती करने से उत्तम खेती और सामान्य परिस्थिओं में प्रति एकड़ 50–60 क्विंटल हरी फल्ली प्राप्त होती है।

बीज की मात्रा

अगेती बुवाई के लिए प्रति एकड़ 40–50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है।

बुवाई का समय

मटर की खेती के लिए अक्टूबर–नवंबर माह का समय उपयुक्त होता है।

बुवाई का तरीका

मटर की बुवाई सीडड्रिल द्वारा की जाती है।

दुरी और गहराई

30 सेंमी. की दूरी पर और बीज की गहराई 5–7 सेंमी. रखनी चाहिये जो मिट्टी की नमी पर निर्भर करती है।

बीज उपचार

बुवाई करने से पहले बीजों को मेंकोजेब या केप्टान या थीरम 3 ग्राम / किलो बीज से बीज उपचारित करना चाहिए। तथा रासायनिक तरीके से बीज उपचार करने के बाद राइजोबियम कल्चर को गुड़ और पानी के घोल के साथ बीज उपचार करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। ध्यान रहे राइजोबियम से उपचारित करने के 4–5 दिन पहले रासायनिक फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए।

खाद एवं रासायनिक उर्वरक

मटर की खेती अच्छे उत्पादन के लिए बुवाई से पूर्व खेत तैयार करते समय वर्मी कम्पोस्ट या अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। रासायनिक उर्वरक की मात्रा नाइट्रोजन 20 किलो, फास्फोरस 25 किलो की मात्रा प्रति एकड़ में प्रयोग करें। और पोटाश की कमी वाले क्षेत्रो में 20 किलो पोटाश/एकड़ प्रयोग करें। ध्यान रासायनिक उर्वरक मिट्टी परिक्षण के आधार पर ही प्रयोग में लाये।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

आरएसएस मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को 2014 के आरएसएस मानहानि मामले के सिलसिले में भिवंडी अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पेश हुए। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन के बाद, जिन्होंने पहले उनके जमानती के रूप में काम किया था, गांधी ने अपनी जमानत के लिए नए जमानती पेश किए। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि यह भिवंडी के एक आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि का मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मूल जमानती, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है, जिसके कारण नए जमानती की आवश्यकता पड़ी। अय्यर ने बताया कि राहुल गांधी और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल कार्यवाही के दौरान उपस्थित थे। अय्यर ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है और उन्हें विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। वकील ने बताया कि उचित समय पर साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

डीएमके के झूठे वादों का जनता देगी जवाब : भाजपा

चेन्नई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने जोर देकर कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों का परिणाम, जिसमें यह भी शामिल है कि कौन सी पार्टी 200 सीटें जीतेगी, मतदाता ही तय करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए नागेंद्रन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की दूसरी चुनावी सभा शहर में आयोजित होने वाली है। गठबंधन पर अपना विश्वास दोहराते हुए नागेंद्रन ने कहा कि जनता तय करेगी कि 200 सीटें कौन जीतेगा। नागेंद्रन ने सत्ताधारी द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) सरकार पर अपने अधिकांश चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके द्वारा किए गए 90 प्रतिशत वादे पूरे नहीं किए गए हैं। जनता को झूठे आश्वासन दिए गए। भाजपा नेता ने आगे दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, और गांजा तस्करी, हत्याओं और लूटपाट की बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया।

यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट नेपाल मॉडल वाली साजिश : पुलिस

नईदिल्ली। दिल्ली पुलिस ने एआई शिखर सम्मेलन में बिना शर्ट पहने प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिमांड मांगते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रदर्शन के समान विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को अदालत में पांच दिन की रिमांड मांगते हुए कहा कि यह देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश थी। भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस के चार नेताओं को शनिवार सुबह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के वकील ने बताया कि वे एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं और उन्होंने भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन किया, जो उनके विरोध करने के अधिकार का प्रयोग था।

एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल का चुनाव पलट दिया!

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से शनिवार को ऐसा झटका लगा जिसने चुनाव से पहले पूरी सियासत को हिला दी है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईआर पर राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच चल रहा टकराव बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अब इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में होगी। अदालत नेक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया कि जिला जज और एडीजे स्तर के बेदाग रिकॉर्ड वाले अधिकारियों को इस काम में लगाया जाए जो लोगों के दावे और आपत्तियों पर फैसला करेंगे। यानी अब वोटर लिस्ट पर अंतिम मोहर सरकार नहीं न्यायपालिका की निगरानी में लगेगी। तो ये फैसला ममता सरकार के लिए बड़ा चुनावी झटका माना जा रहा है क्योंकि जिस प्रक्रिया पर सत्ता का नियंत्रण माना जा रहा था वही अब कोर्ट की निगरानी में चली गई है। अब साफ संदेश यह है कि अब चुनावी खेल नियमों से होगा ना कि सत्ता की शर्तों पर।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए द्रमुक ने कसी कमर

चेन्नई। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) ने अपनी चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। शनिवार को पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनावों के लिए अपने सहयोगियों के साथ सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू करने हेतु एक उच्च स्तरीय सात सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष टी.आर. बालू इस महत्वपूर्ण समिति की कमान संभालेंगे। समिति में पार्टी के उन दिग्गजों को शामिल किया गया है जिन्हें गठबंधन की राजनीति और चुनावी गणित का लंबा अनुभव है। तमिलनाडु विधानसभा सत्र 20 फरवरी को समाप्त होने के साथ ही द्रमुक अपनी बूथ समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने और सदस्यता अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। द्रमुक ने कहा कि सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। पार्टी के कोषाध्यक्ष बालू इस समिति के प्रमुख होंगे।

पीएम मोदी-लूला दा सिल्वा के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता

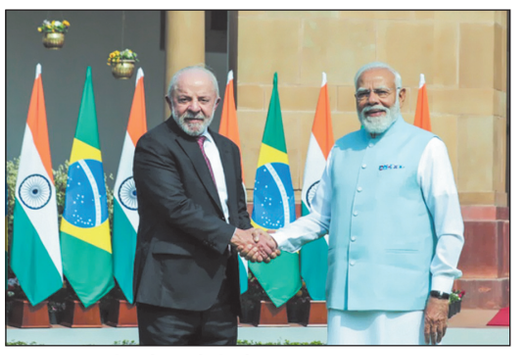

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रेगा ने कहा कि राष्ट्रपति लूला और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छी समझ और दोस्ती है, जिससे दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति लूला भारत की राजकीय यात्रा पर 11 कैबिनेट मंत्रियों, 300 से अधिक कारोबारियों और 50 सीईओ के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक की।

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। हम अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा ट्रेड सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है; यह भरोसे की झलक है। राष्ट्रपति के साथ आया बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल इसी भरोसे को दिखाता है। इंडिया-मर्कोसुर व्यापार अनुबंध का विस्तार हमारे इकोनॉमिक सहयोग को और मजबूत करेगा। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ-साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि हम ब्राज़ील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर काम कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपरकंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे एरिया में भी अपने सहयोग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि टेक्नोलॉजी सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए और शेयर्ड प्रोग्रेस के लिए एक ब्रिज बननी चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रपति लूला और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपने पिछले वर्ष मेरा ब्राजील में जिस तरह स्वागत किया था, मैं उसी तरह आप सभी का अभिनंदन करता हूं... राष्ट्रपति लूला की दूर दृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का भारत और ब्राजील के रिश्तों को लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते कुछ वर्षों में मुझे आपसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है... इनके इस दौर ने ऐतिहासिक एआई समिट की शोभा बढ़ाई और हमारी रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा भी दी है। मैं दोनों देशों के संबंधों के प्रति कमिटमेंट के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को राजधानी में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की और नई दिल्ली और ब्रासीलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके मार्गदर्शन की सराहना की। शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकातों से संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई। भारत की राजकीय यात्रा पर आए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात का सम्मान मिला। रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्नेहपूर्ण भाव और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि आज बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकातों से हमारे संबंधों को नई गति मिलेगी।

एक न्यूज चैनल से बातचीत में लूला दा सिल्वा ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर है, जिसे 30-40 अरब तक बढ़ाना चाहिए। वे 260 ब्राजीलियाई व्यवसायियों के साथ आए हैं ताकि अंतरिक्ष, रक्षा, फार्मा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी हो। वहीं ब्राजील की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर भारत में प्लांट भी खोलेगी।

भारत और ब्राजील ने साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 15.21 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें भारत का निर्यात 8.35 अरब डॉलर और ब्राजील से आयात 6.85 अरब डॉलर रहा। वहीं ब्राजील में भारतीय निवेश 15 अरब डॉलर से ज्यादा रहा।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। जिसमें महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ खनिज, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे क्षेत्रों पर खास केंद्रित है। पीएम मोदी के न्योते पर लूला दा सिल्वा भारत के दौरे पर पहुंचे हैं। वे 18-22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वे 22 फरवरी को दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे।

ट्रंप टैरिफ रद्द, तो अमेरिका डील में जल्दबाज़ी क्यों?

खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को सवाल उठाया कि क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की विदेश नीति अस्पष्ट है या उसने अमेरिका के सामने एकतरफा आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सवाल अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को खारिज करने के बाद उठाया गया। एक्स पर एक पोस्ट में, खरगे ने पूछा कि केंद्र ने अंतरिम व्यापार समझौते में जल्दबाजी करने से पहले अमेरिकी अदालत के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया, जिसे उन्होंने जाल समझौता कहा।

खरगे ने समझौते के संयुक्त वक्तव्य की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें कई अमेरिकी निर्यातों पर शून्य टैरिफ शामिल हैं, जिससे भारत की कृषि को अमेरिकी वस्तुओं के लिए प्रभावी रूप से खोल दिया गया है, 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों के आयात की योजना है, रूसी तेल की खरीद पर रोक है जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंच सकता है, और कई डिजिटल कर रियायतें शामिल हैं।

खरगे के एक्स पोस्ट में लिखा था कि अस्पष्ट विदेश नीति या एकतरफा आत्मसमर्पण? मोदी सरकार ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया, इससे पहले कि वह जल्दबाजी में एक ऐसे धोखेबाज़ समझौते में फंस गई, जिससे भारत से भारी रियायतें हासिल की गईं? संयुक्त बयान में भारत को निर्यात होने वाले कई अमेरिकी उत्पादों पर शून्य टैरिफ की बात कही गई थी, जिससे भारत की कृषि को अमेरिकी वस्तुओं के लिए लगभग खोल दिया गया था, 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान आयात करने की योजना थी, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता थी और डिजिटल क्षेत्र में कई कर रियायतें थीं।

उन्होंने आगे मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करें कि किसने सरकार पर भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने के लिए दबाव डाला। खरगे ने 140 करोड़ भारतीयों की गरिमा की रक्षा करने और किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने वाले एक निष्पक्ष व्यापार समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया। एक्स पोस्ट में आगे लिखा था कि मोदी जी को भारतीयों के सामने खड़े होकर सच बताना होगा। किसने या किस बात ने आप पर भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने का दबाव डाला? क्या यह एपस्टीन फाइल्स का मामला था? क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक ऐसा निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करे?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस का करारा हमला

भारत-अमेरिका के बीच हाल ही में हुए अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर देश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह समझौता देश के हितों के साथ समझौता है और प्रधानमंत्री की %छवि बचाने% की जल्दबाजी के कारण भारत को एक कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर शनिवार को पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए यह सवाल भी किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें? रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''कल अमेरिका के उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी शुल्क नीति को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता घोषणा के अनुसार जारी रहेगा और उन्होंने 10 मई 2025 को भारतीय निर्यात पर शुल्क बढ़ाने की धमकी देकर व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था।''

उन्होंने कहा, ''दो फरवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले घोषणा की थी कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुकी है। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के चलते तथा उनके अनुरोध पर, तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई।'' रमेश ने सवाल किया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें? कांग्रेस नेता ने कहा, ''उस दोपहर लोकसभा में ऐसा क्या हुआ था, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को इतना व्याकुल कर दिया कि उन्होंने 'व्हाइट हाउस' (अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) में अपने 'अच्छे मित्र' से संपर्क कर ध्यान भटकाने वाली स्थिति पैदा की?'' उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अपनी नाजुक छवि बचाने को लेकर इतने व्यग्र न होते और केवल 18 दिन और प्रतीक्षा कर लेते।

खेल
प्रमुख समाचार

सुपर 8 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला आज

अहमदाबाद। ग्रुप चरण के चारों मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम अब टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका की कड़ी चुनौती के लिए तैयार है। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा की बदली हुई बल्लेबाजी रणनीति की असली परीक्षा होगी।

भारत को ग्रुप स्टेज में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सुपर 8 में मुकाबला पूरी तरह अलग होगा। दक्षिण अफ्रीका के पास कैगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, मार्को जानसन, केशव महाराज और कप्तान एडेन मार्कराम जैसे मजबूत गेंदबाज हैं, जो भारत की बल्लेबाजी की कड़ी परीक्षा लेने को तैयार हैं। पिछले दो महीनों में दोनों टीमें छठी बार आमने-सामने होंगी।

सलामी बल्लेबाज ईशान किशन (दो अर्धशतक, 202 का स्ट्राइक रेट) को छोड़ दें तो शीर्ष क्रम में बाकी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अभिषेक शर्मा लगातार तीन मैच में शून्य पर आउट हुए हैं।तिलक वर्मा ने 24 गेंद में 25, 21 गेंद में 25 और 27 गेंद में 31 रन की पारियां खेलीं — लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 120 के आसपास रहा, जो उनके करियर औसत (141) से काफी कम है।

सूर्यकुमार यादव ने अमेरिका के खिलाफ 84* रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उसके बाद लय में नजर नहीं आए। उनका मौजूदा स्ट्राइक रेट 136 है, जो उनके करियर औसत 163 से कम है। ऐसे में बड़े शॉट की बजाय परिस्थितियों के अनुसार स्थिर बल्लेबाजी की रणनीति कितनी कारगर होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। भारत रन गति बनाए रखने के लिए हार्दिक पांड्या (स्ट्राइक रेट 155) और शिवम दुबे (स्ट्राइक रेट 178) पर काफी निर्भर रहा है। टीम को एक बार फिर इन दोनों से आक्रामक योगदान की उम्मीद होगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

अप्रैल में लागू हो सकता है भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता

नईदिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौता अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और समझौते को अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मार्च के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली आ सकता है। इस दौरान समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। हालांकि दौरे की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसी बीच भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम रविवार को वाशिंगटन के लिए रवाना हो रही है। यह टीम 23 फरवरी से शुरू होने वाली बैठक में समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देगी।

शुद्ध बाजार उधारी 2026-27 में जीडीपी के 3% तक आएगी

मुंबई। सरकार की शुद्ध बाजार उधारी में गिरावट से निजी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी मासिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, केंद्र सरकार की शुद्ध बाजार उधारी वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी के तीन प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव है, जो महामारी-पूर्व स्तर की ओर धीरे-धीरे वापसी का संकेत है। इस साल के लिए 17.3 लाख करोड़ रुपए की सकल बाजार उधारी का प्रस्ताव कई लोगों की अपेक्षाओं से अधिक माना गया है। इससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों और बजट दिवस पर बाजार में गिरावट को लेकर चिंता हुई। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध बाजार उधारी वित्त वर्ष 2019-20 में 4.73 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) थी।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ रद्द

वॉशिंगटन। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर लगाए गए व्यापक आयात शुल्कों को 6-3 के बहुमत से रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश John Roberts द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए ये शुल्क कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फैसले के बाद 20 फरवरी को जारी घोषणा में ट्रंप ने कहा कि 24 फरवरी 2026 से 150 दिनों के लिए अमेरिका में आयात होने वाले सभी सामान पर 10 प्रतिशत का अस्थायी आयात शुल्क लगाया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी, क्योंकि पहले लगाए गए भारी पारस्परिक शुल्क अब घटकर 10 प्रतिशत रह जाएंगे। गौरतलब है कि अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क लगाया था।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था दिसंबर तिमाही में सुस्त रही

वाशिंगटन। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार दिसंबर तिमाही में सुस्त होकर 1.4 प्रतिशत रह गई। यह सितंबर तिमाही की 4.4 प्रतिशत और उससे पहले की तिमाही की 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले काफी कम है। वाणिज्य विभाग की तरफ से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी और उपभोक्ता खर्च में आई कमी वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की सुस्ती का मुख्य कारण रही। उपभोक्ता खर्च में केवल 2.2% की वृद्धि हुई, जो सितंबर तिमाही की 3.5 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले काफी कम है। यह रिपोर्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश करती है, जहां वृद्धि दर स्थिर है लेकिन रोजगार के नए अवसर नहीं पैदा रहे हैं। साल 2025 में आर्थिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर रही।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील सिर्फ व्यापार नहीं, विकास के लिए भी अहम

टी टी राम मोहन

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जिसके लिए अंतरिम करार के एक ढांचे पर सहमति बनी है, उसकी आलोचना करने वाले भी कम नहीं हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे आत्मसमर्पण करार दिया है। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कई लोग विस्तृत ब्योरे की प्रतीक्षा में हैं और समझौते को अंतिम रूप मिलने के बाद वे कह सकते हैं कि यह समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है।

हमें कुछ बातों को लेकर स्पष्ट होना होगा। पहली बात कोई देश जो ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार वार्ता कर रहा हो उसे यही उम्मीद करनी चाहिए कि समझौता अमेरिका के पक्ष में झुका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका के आर्थिक समीकरणों को दुरुस्त करने की है। वह इसके लिए अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने पर दृढ़ हैं।

विश्व युद्ध के बाद की पूरी अवधि में अमेरिका कई व्यापार साझेदारों को खुशी-खुशी बढ़त दे रहा था। वह मानता रहा है कि आर्थिक रूप से वह काफी मजबूत है। वह मानता था कि समृद्धि को शेष विश्व के साथ साझा करना विश्व शांति में मददगार होगा और दुनिया को वामपंथ से भी बचाए रखेगा।

अब ऐसा नहीं है। ट्रंप साल 2016 में यह कहकर सत्ता में आए कि अब वक्त आ गया है कि व्यापारिक रिश्तों को अमेरिका के हितों के हिसाब से तय किया जाए। वह ऐसा कर नहीं सके क्योंकि उनकी पहलों को उनकी ही कैबिनेट के उन सदस्यों का साथ नहीं मिला जो हालात को जस का तस रखना चाहते थे। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप वह गलती नहीं दोहराना चाहते थे। उन्होंने अपने वफादारों

को सरकार में शामिल किया जो उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

गत जुलाई में ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा, 'अमेरिका को व्यापार (और सैन्य मामलों!) में, दशकों से मित्रों और शत्रुओं दोनों द्वारा ठगा गया है। इसकी कीमत खरबों डॉलर रही है, और यह अब और टिकाऊ नहीं है। और कभी था भी नहीं! इसलिए किसी भी व्यापार समझौते में, लाभ अमेरिका का ही होगा।'

दूसरी बात, हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि अमेरिका के साथ रिश्ते इस बात पर निर्भर हैं कि ऐसा व्यापार समझौता हो जो अमेरिका को स्वीकार्य हो। यदि व्यापार समझौता नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा, हर क्षेत्र में अमेरिकी शत्रुता को आमंत्रित करना। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय, हर राष्ट्र के सामने एक विकल्प होता है: वह क्या चाहता है, अमेरिका उसका मित्र बने या शत्रु?

यूरोपीय संघ के साथ ट्रंप का समझौता इसका सटीक उदाहरण है। यूरोपीय संघ के लिए मुद्दा केवल अमेरिकी बाजार तक पहुंच का नहीं था। उसे यूक्रेन विवाद में भी अमेरिका की मदद की आवश्यकता थी। इसके तहत अहम हथियारों और खुफिया जानकारियों के साथ-साथ उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में अमेरिकी सहयोग, सब शामिल था। अमेरिका के साथ रक्षा रिश्तों को बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने ऐसी शर्तें स्वीकार कर लीं जो शर्मनाक थीं।

अब यूरोपीय संघ के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 15 फीसदी का शुल्क लगता है। इसके अलावा स्टील, एल्युमीनियम और कॉपर निर्यात पर 50 फीसदी का शुल्क लागू है। कारों का निर्यात कोटा के अधीन है। यूरोपीय संघ ने अगले तीन साल में 750 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की हामी भरी है और वर्ष 2029 तक अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है।

यूरोपीय संघ समस्त अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं के आयात पर शुल्क समाप्त करेगा और अमेरिकी समुद्री और कृषि उत्पादों को प्राथमिकता वाली पहुंच देगा। इससे अधिक समर्पण भला क्या होगा? ट्रंप ने ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भी ऐसा ही एकतरफा समझौता किया। ये सभी अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।

भाजपा समेत विभिन्न संगठनो ने मनाया सीएम साय का जन्मदिन

रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न सेवा एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके दीर्घायु, शतायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई

रायपुर। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, जिला रायपुर द्वारा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विभिन्न सेवा एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके दीर्घायु, शतायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई।

प्रात: 9:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के रायपुर आगमन पर हेलीपैड में उनका आत्मीय स्वागत किया गया तथा उन्हें मोतीचूर के लड्डुओं से तौलकर शुभकामनाएं अर्पित की गईं। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने जिले के सभी पदाधिकारियों एवं मंडल प्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री जी का परिचय भी कराया।

प्रात: 11 बजे जिला अस्पताल पंडरी में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति रही। यह कार्यक्रम जिला अनुसूचित जाति मोर्चा एवं महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया। जिसमें महिला मोर्चा अध्यक्ष कृतिका जैन एवं पंकज जगत के साथ मोर्चा के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे वहीं ओबीसी मोर्चा द्वारा आयुर्वेदिक महाविद्यालय में फल वितरण किया गया। जिसमें जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर एवं अखिलेश कश्यप और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

महिला मोर्चा द्वारा काली मंदिर में हवन-पूजन कर मुख्यमंत्री जी के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई। इसी प्रकार बीरगांव स्थित बंजारी मंदिर में बीरगांव मंडल एवं मां बंजारी मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा हवन-यज्ञ किया गया। रेलवे स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर में भी पूजा-अर्चना की गई। जिले के सभी मंडलों एवं वार्डों में कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने क्षेत्र में सेवा एवं धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से मुख्यमंत्री साय का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया।

इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कामना की।

जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री साय का सादगीपूर्ण एवं जनसेवा समर्पित जीवन हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है ।

कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से अकबर अली, सुभाष अग्रवाल, नवीन शर्मा, गुंजन प्रजापति, तुषार चोपड़ा, जितेंद्र धुरंधर, संजय तिवारी, श्रद्धा मिश्रा, रंभा चौधरी, सरोज साहू, पन्ना दुबे,अनीता देवांगन, चूड़ामणि निर्मलकर, अनूप खेलकर, मधुसूदन शर्मा, सुरेश पटेल, शिवजलम दुबे, पुष्पेंद्र उपाध्यक्ष, रोहित द्विवेदी, राजकुमार राठी, विकास मिश्रा, चंद्र विशाल भूरा, रोहित भारद्वाज, अभिषेक श्रीवास्तव, रविंद्र सिंह ठाकुर, तोषण कुमार साहू, राहुल जैन, सदाशिव सोनी, 20 मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गंदेचा, दलविंदर बेदी, राम प्रजापति, संदीप जंघेल, केदार धनगर, सचिन सिंघल, संतोष सोनी, सुनील कुकरेजा, अभिषेक तिवारी, दिनेश तिवारी, चैतन्य टावरी, पुरुषोत्तम मोवले, विनय जैन, विशेष शाह, योगेश साहू, भोला साहू, मनोज जोशी, भीमवंत निषाद, मनीष नागोड़े, भागीरथ यादव एवं मोर्चों के जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी, कृतिका जैन, अखिलेश कश्यप, पंकज जगत, ओम प्रकाश साहू, जीशान सिद्दीकी उपस्थित रहे। सहित जिला एवं मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

तकनीक और विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक: पाण्डेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पाण्डेय ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक 'एआई समिट' के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अभद्र और अमर्यादित प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार किया है। शताब्दी पाण्डेय ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और अद्यतन विकास के गौरव को शर्मसार करने वाली घटना बताया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने कहा कि जहाँ आज पूरी दुनिया भारत की तकनीकी शक्ति का लोहा मान रही है और नई दिल्ली 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रही है, वहीं कांग्रेस का यह 'नग्न प्रदर्शन' उसकी पिछड़ी और विकास-विरोधी सोच को दर्शाता है। राजनीति में विरोध के कई सभ्य तरीके होते हैं, लेकिन सड़कों पर उतरकर इस तरह का अश्लील आचरण करना कांग्रेस के राजनीतिक दीवालिएपन और वैचारिक पतन की पराकाष्ठा है। यह न केवल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, बल्कि विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास भी है। कांग्रेस आलाकमान को इस अमर्यादित कृत्य के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

भाजयुमो ने किया कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव

कांग्रेस भारत की वैश्विक छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है : टिकरिहा

रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिट में युवा कांग्रेस द्वारा किए गए शर्मनाक, अमर्यादित एवं अभद्रतापूर्ण कृत्य के विरोध में शनिवार को भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन का घेराव किया। लगभग 2 हजार की संख्या में पहुँचे भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके पूर्व भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया था।

इस दौरान भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस का नग्न प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के खत्म होते वजूद का प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई शिखर सम्मेलन में अभद्र एवं अमर्यादित प्रदर्शन कर कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को पुन: साबित किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति देश से बड़ी है। कांग्रेस के किए गए अमर्यादित कृत्य के लिए जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय गौरव से ऊपर अपने राजनीतिक हितों को रखती है।

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। भारत पुन: विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा देश की छवि को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

एआई समिट में नग्न प्रदर्शन सोची-समझी साजिश : देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने नई दिल्ली में आहूत एआई समिट के दौरान शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन को भारत को अपमानित करने की एक सोची-समझी साजिश बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी राजनीति के एक नए निचले स्तर पर गिर गए हैं, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजनीतिक पोस्टर लेकर दुनिया के सबसे बड़े %एआई इम्पैक्ट समिट% में निर्वस्त्र होने का निर्देश दिया।

श्री देव ने कहा कि यह प्रदर्शन कांग्रेस के घोर पतन, निर्लज्जता और मानसिक दीवालिएपन का परिचायक है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि राहुल गांधी के उकसावे पर की गई यह घिनौनी हरकत कांग्रेस पार्टी के पूर्ण वैचारिक पतन को उजागर करती है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, प्रगति और राष्ट्र निर्माण के लिए खड़ा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केवल व्यवधान, बाधा और नकारात्मकता का प्रतीक बन गई है। श्री देव ने आरोप लगाया कि यह स्पष्ट है कि कांग्रेस ने %एआई इम्पैक्ट समिट% को बदनाम करने की साजिश बहुत पहले ही रच ली थी। राहुल गांधी के इशारे पर लोगों को इकट्ठा किया गया, उन्हें शिखर सम्मेलन के लिए पंजीकृत कराया गया और फिर इस अपमानजनक कृत्य के लिए उकसाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि तकनीक के विकास के मामले में दुनिया भारत का लोहा मान रही है लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने देश की छवि को नुकसान पहुँचाने का रास्ता चुना और पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा करने की सक्रिय कोशिश की है।एकमात्र कारण यह है कि राहुल गांधी भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते।

भारत की प्रतिष्ठा पर आघात, राहुल और कांग्रेस देश से माफी मांगें : साव

रायपुर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एआई समिट जैसे वैश्विक आयोजन के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए नग्न प्रदर्शन को अत्यंत शर्मनाक और राष्ट्रविरोधी करार दिया है। श्री साव ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस द्वारा किया गया यह नग्न प्रदर्शन न केवल अमर्यादित है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है।

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री साव ने कड़े शब्दों में इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि जब विश्व भर से कई राष्ट्र अध्यक्ष, प्रतिनिधि और दिग्गज एआई समिट के लिए भारत आए हुए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन के मंच पर इस तरह का अमर्यादित प्रदर्शन कांग्रेस की भारत विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। उनके निर्देशों पर ही कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे कार्यों में संलिप्त है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। यह कांग्रेस का राष्ट्रविरोधी चेहरा एक बार फिर जनता के सामने उजागर करता है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस शर्मनाक कृत्य के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री साव ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रके सम्मान से समझौता करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि इस शर्मनाक प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का एजेंडा विकास में बाधा डालना और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को कम करना है। समिट के दौरान किया गया यह प्रदर्शन उनके राष्ट्र-विरोधी रवैये का प्रमाण है। भारत आज तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है, और ऐसी घटनाओं से देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन कर अपनी स्तरहीन और राष्ट्र विरोधी राजनीति से बाज आना चाहिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

रायपुर। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के सामने सड़क में बैठ कर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजीव भवन घेरने आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया और नरेन्द्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, दीपक मिश्रा, महेन्द्र छाबड़ा, सुबोध हरितवाल, कन्हैया अग्रवाल, युकां अध्यक्ष आकाश शर्मा, रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन, रायपुर ग्रामीण अध्यक्ष राजेन्द्र पप्पू बंजारे, शांतनु झा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, अशोक राज आहूजा, शिव सिंह ठाकुर, डॉ. अजय साहू, सत्यप्रकाश सिंह, सौरभ साहू, परवेज अहमद, ऋषभ चंद्राकर, विनोद तिवारी, सुनील कुकरेजा, दिलीप चौहान, राजेश चौबे, नरेन्द्र ठाकुर, सद्दाम सोलंकी, अशोक चतुर्वेदी, अजय अग्रवाल, कमलेश मिश्रा, पल्लवी सिंह, करूणा कुर्रे, दिनेश तिवारी, शब्बीर खान, योगेश तिवारी, अभिषेक कसार, दिनेश निर्मलकर, अमितेश भारद्वाज, गीता सिंह, बंशी कन्नौजे, लक्ष्मी देवांगन मौजूद थे।

कनेक्ट सेंटर के पदाधिकारियों को लोकसभावार जिम्मेदारी दी

रायपुर। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश में आधुनिक कनेक्ट सेंटर बनाया गया है जिसका संचालन के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कनेक्ट सेंटर के नवनियुक्त पदाधिकारियों को लोकसभावार दायित्व सौंपा एवं नियुक्ति पत्र दी। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक मार्गदर्शन दिये। कनेक्ट सेंटर की उपयोगिता की जानकारी दी। एआईसीसी महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एवं वरिष्ठ नेतागण आने वाले दिनों में नवनिर्मित कनेक्ट सेंटर का उद्घाटन करेंगे। सरगुजा लोकसभा प्रभारी दिनेश निर्मलकर, रायगढ़ लोकसभा प्रभारी अमितेश भारद्वाज, जांजगीर-चांपा लोकसभा प्रभारी गीता सिंह, कोरबा लोकसभा प्रभारी बंशी कन्नौजे, बिलासपुर लोकसभा प्रभारी लक्ष्मी देवांगन, मनोज सोनकर, राजनांदगांव लोकसभा प्रभारी कविता वर्मा, सुरेश वर्मा, दुर्ग लोकसभा प्रभारी जयप्रकाश साहू, रायपुर लोकसभा प्रभारी प्रेमलता बंजारे, महासमुंद लोकसभा प्रभारी अंशुल मिश्रा, बस्तर लोकसभा प्रभारी कामरान अंसारी, कांकेर लोकसभा प्रभारी शीतल कुलदीप, माधव छुरा को नियुक्त किया गया है। बैठक में कनेक्ट सेंटर के चेयरमेन एवं प्रदेश महामंत्री दीपक मिश्रा, कन्हैया अग्रवाल, अशोक राज आहूजा, शिव सिंह ठाकुर, डॉ. अजय साहू, सुनील कुकरेजा, दिलीप चौहान, अशोक चतुर्वेदी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया पूरी, 25 लाख नाम हटे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। निर्वाचन विभाग ने इसके उपरांत राज्य की अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन कर दिया है। इस व्यापक अभियान के दौरान फर्जी, दोहराव वाले और संदिग्ध मतदाताओं के नामों की पहचान कर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, जिससे मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनाया जा सका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने अंतिम सूची जारी होने की जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रुक अभियान के दौरान लगभग 24 लाख 99 हजार से अधिक नाम सूची से हटाए गए हैं। संशोधित और अंतिम प्रकाशन के अनुसार अब प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,30,914 दर्ज की गई है। उन्होंने अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले नागरिकों, निर्वाचन कर्मियों और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया।निर्वाचन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,12,30,737 थी। प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 1,84,95,920 रह गई थी। ड्राफ्ट सूची पर प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली जारी की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1,87,30,914 हो गई।

उपभोक्ता संरक्षण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने उपभोक्ता संरक्षण विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.पी. साही, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, मध्यप्रदेश, गोवा, बिहार, झारखंड उत्तरप्रदेश सहित आठ राज्यों के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.पी. साही ने कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी एवं विधिक सुधारों की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में जागरूकता एवं तकनीकी पहलुओं की प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

रमजान के अवकाश को निरस्त करना बदले की भावना: विजय

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को प्रतिवर्ष रमजान के महीने में कार्यालय बंद होने के 1 घंटा पूर्व अवकाश की पात्रता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही वर्ष 2005, 2008 एवं 2015 तक जारी किया गया था। आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान ने बताया है कि शासन के अधिकृत सुविधा हैण्ड बुक में रमजान के महीने में अवकाश का उल्लेख प्रतिवर्ष के लिए रमजान प्रारंभ होने से रमजान समाप्ति तक किया गया है। 19 फरवरी को रमजान का महीना प्रारंभ होते ही इस आदेश के संबंध में चर्चा प्रारंभ हो गई। राज्य सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों से बदले की भावना व धार्मिक राग द्वेष के कारण पूर्व में स्वयं के सरकारों द्वारा जारी आदेश को निरस्त करने का आदेश 20 फरवरी को जारी करते हुए मीडिया समाचार पत्र में जारी 1 घंटे के रमजान के अवकाश को भ्रामक एवं आधारहीन निरूपित किया है। कहीं ना कहीं जाति धर्म संप्रदाय में खुलेआम बाटा जा रहा है। यह निंदनीय एवं संविधान के विपरीत है। रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान ने वक़्फ़ बोर्ड चेयरमेन सलीम राज पर तंज करते हुए कहा सरकार की इतनी चापलूसी भी सही नही, समाज के खिलाफ लगातार बयान बाजी करते करते समाज मे तो सम्मान है नही सरकार भी अब मजाक बनाने लग गई है ।

वन मंत्री कश्यप मर्दापाल में भूमिपूजन और मेला मंड़ई कार्यक्रम में हुए शामिल

ग्रामीण अंचल के जरूरतों को पूरा किया जाएगा

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज कोंडागांव जिले के मर्दापाल में आयोजित भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने क्षेत्रवासियों को 2 करोड़ 18 लाख 47 हजार रुपए की लागत वाले कुल 36 विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही वन मंत्री ने मर्दापाल में भूमिपूजन कार्यक्रम से पहले गांव के मड़ई मेला में सम्मिलित होकर भंगा राम मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की।

वन मंत्री कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी ग्रामवासियों को पारंपरिक भंगाराम माता मावली माघ मड़ई मेला की शुभकामनाएं दीं और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास और शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आगे भी ग्रामीण अंचल के जरूरतों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना को और अधिक प्रभावी बनाया गया है जिसके तहत अब लोगों को 125 दिन की रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और एक सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाएगा।

वन मंत्री ने शिविर में पंचायत विभाग के विकसित भारत जीरामजी योजना पर आधारित स्टॉल के साथ- साथ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया और ग्रामीणों से कहा कि विभागों के स्टॉल में पहुंचकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जनपद पंचायत की अध्यक्ष मती अनिता कोर्राम ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी दी और अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।वन मंत्री केदार कश्यप ने मर्दापाल में विभिन्न ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण एवं सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार हेतु कुल 218.47 लाख रुपये की लागत से 36 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच, आंगनबाड़ी भवन, सीसी सड़क, नाली निर्माण तथा पुलिया निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा कई गांवों के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे।

कलेक्टर ने परीक्षा केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

रायपुर। जिलाधीश डॉ गौरव सिंह,निगम आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती की टीम ने शनिवार को दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने दानी स्कूल परीक्षा केंद्र तथा शहीद संजय यादव शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, संजय नगर स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छता तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा परीक्षा शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी करते हुए परीक्षाओं के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन, जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.